वर्ष 12 • अंक 287 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 20 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 4

दवा फर्मों के लिए नैतिकता निरीक्षकों की तैयारी

निर्मला सीतारमण ▶▶ पृष्ठ 12

तमिल शरणार्थियों को भी मिलेगी नागरिकता

एक नज़र

दावोस में जुटेंगे शीर्ष नेता और उद्योगपति

दुनिया की कई अमीर और ताकतवर हस्तियां इस सप्ताह स्विटजरलैंड के रिजॉर्ट शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। 20 जनवरी से शुरू हो रहा यह सम्मेलन पांच दिन चलेगा। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, अफगानिस्तान के अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी हिस्सा लेंगे। साथ ही इसमें भारत के कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, 100 से अधिक सीईओ, फिल्म अभिनेत्री दीपिका पडुकोणे और सद्गुरु के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। पृष्ठ 4

तिमाही नतीजों, बजट की उम्मीदों से बाजार को दिशा

कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा आम बजट की उम्मीदों से इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल तय होगी। इस सप्ताह कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐक्सिस बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के तिमाही परिणाम आने हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर शेयर बाजारों की हालिया तेजी की प्रमुख वजह हैं। आने वाले समय में निवेशक सतर्क रहेंगे क्योंकि बाजार सर्वकालिक उच्च स्तर पर चल रहे हैं।

बैंक कर्ज दोगुना करने की जरूरत : एसबीआई चेयरमैन

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने रविवार को कहा कि अगर भारत को 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करना है तो बैंकिंग क्रेडिट को मौजूदा स्तर से दोगुना करना होगा। कुमार ने कहा कि इस समय भारत के बैंकिंग क्रेडिट का बकाया करीब 99 लाख करोड़ रुपये है और भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले 5 साल में कर्ज कम से कम दोगुना करने की जरूरत है। पृष्ठ 4

पीएसयू के एजीआर भुगतान की समयसीमा पर विचार

दूरसंचार विभाग इस मुद्दे पर गौर कर रहा है कि क्या दूरसंचार कंपनियों पर सांविधिक बकाये के भुगतान के लिए तय 23 जनवरी की समयसीमा गैर-दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू होती है। एजीआर को लेकर उच्चतम न्यायालय में चले विवाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पक्ष नहीं थे। विभाग के सूत्रों कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद पीएसयू से भी सांविधिक बकाया चुकाने को कहा गया है। परंतु सवाल यह है कि क्या 23 जनवरी की समयसीमा कानूनी रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों पर भी लागू होती है जो सीधे इस विवाद में पक्ष नहीं थे।

उड़द का आयात कोटा जून तक बढ़ाने की योजना

सरकार की उड़द दाल आयात की समयसीमा इस साल जून तक बढ़ाने की योजना है। वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख टन उड़द आयात कोटे की समयसीमा को तीन महीने बढ़ाकर जून तक किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि घरेलू स्तर पर उड़द की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठा सकती है। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ ने सरकार से उड़द पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने की मांग की है। खरीफ फसल को नुकसान से देश में उड़द उत्पादन करीब 50 फीसदी कम रहने की आशंका है।

रिजर्व बैंक की बैठक में उठेगा अंतरिम लाभांश का मुद्दा!

रिजर्व बैंक के बोर्ड की अगली बैठक में अंतरिम लाभांश के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के 3.3 फीसदी के तय लक्ष्य पर खरा उतरने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है और केंद्रीय बैंक से अंतरिम लाभांश मिलने पर उसे मदद मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले रिजर्व बैंक के बोर्ड की कम से कम एक बैठक होगी जिसमें अंतरिम लाभांश का मुद्दा उठाया जा सकता है।

आज का सवाल

क्या संपत्तियों की बिक्री से पूरा होगा विनिवेश का लक्ष्य

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या आरआईएल के नतीजों से बाजार होगा निराश? हां **41.67%** नहीं **58.33%**

संपत्ति बेच विनिवेश लक्ष्य होगा पूरा!

मार्च से पहले कई सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों के मुद्रीकरण की हो रही तैयारी

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 19 जनवरी

चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों का निजीकरण पूरा होने की संभावना नहीं है, ऐसे में केंद्र सरकार को संपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिये 2019-20 में 1.05 लाख करोड़ रुपये के महत्त्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार सरकार के साथ ही संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की कई संपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया के अग्रिम चरण में है। इन संपत्तियों में कार्यालय की जगह, अपार्टमेंट, फैक्टरियां, जमीन, बिजली पारेषण संपत्तियां, गैस पाइपलाइन, दूरसंचार संपत्तियां आदि शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कई विभागों और सार्वजनिक उपक्रम संपत्तियों के मुद्रीकरण में तेजी लाने में जुटे हैं।'

सरकार के साथ काम कर रही भारत की प्रमुख परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों में से एक से जुड़े सूत्र ने कहा कि 31 मार्च, 2020 से पहले करीब 1 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों की बिक्री की जा सकती है। उन्होंने कहा, 'इन संपत्तियों की बिक्री करना काफी आसान होगा, क्योंकि इनमें खरीदार की काफी दिलचस्पी हो सकती है और जोखिम भी कम है।'

- परिसंपत्ति बिक्री में तेजी के लिए विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को सजग किया गया
- सूत्रों ने कहा, करीब एक लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति बेची जा सकती है
- केंद्रीय उपक्रमों की परिसंपत्ति बिक्री का मुनाफा सरकार को लाभांश के रूप में मिलेगा

हालांकि एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि संपत्तियों की बिक्री के लिए लक्ष्य तय करना काफी कठिन है। अधिकारी ने कहा, 'केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों के मामले में संपत्ति की बिक्री से मिलने वाला पैसा संबंधित कंपनी के पास जाएगा। उसके बाद कंपनी लाभांश के तौर पर सरकार को भुगतान करेगी। अगर वह घाटे वाली कंपनी होगी तो कंपनी अधिनियम के तहत वह लाभांश नहीं दे सकती है। ऐसे में हम संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम का लक्ष्य तय नहीं कर सकते हैं।'

केंद्र की संपत्ति मुद्रीकरण के लिए दो तरह की योजना है। नीति आयोग ने जो योजना बनाई है, उनमें पांच से छह सरकारी स्टेडियम, बिजली पारेषण संपत्तियों, गेल की गैस पाइपलाइन, बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्तियों के साथ ही दार्जिलिंग, कालका-शिमला और नीलगिरि हेरिटेज रेल परिचालन शामिल हैं।

एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा कि इन परिसंपत्तियों के बारे में शीर्ष स्तर पर चर्चा चल रही है और सभी संबंधित विभागों में काम चल रहा है। केवल विरासत रेल मार्गों पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) भी इस पर विचार कर रहा है। ये कपंनियों की गैर प्रमुख परिसंपत्तियां हैं जिन्हें रणनीतिक बिक्री, सार्वजनिक उपक्रमों के बीच विलय या बंद करने के लिए चिह्नित किया गया है।

इन परिसंपत्तियों में भूखंड, कारखाने, अपार्टमेंट और दफ्तर की जगह शामिल हैं जो विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी हैं। इनमें प्रोजेक्ट ऐंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब, ब्रिज ऐंड रूफ कंपनी, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड और कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। भूखंड और फैक्टरी परिसंपत्तियां देश के कई हिस्सों में फैली हैं जबकि दफ्तर की ज्यादातर जगह और अपार्टमेंट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और मुंबई/नवी मुंबई में हैं।

अब तक दीपम ने केवल 18,095 करोड़ रुपये जुटाए हैं जो विनिवेश के पूरे साल के बजट लक्ष्य का महज 17 फीसदी है।

लाभांश वितरण कर हो सकता है खत्म!

दिलाशा सेठ और सुदीप्त दे
नई दिल्ली, 19 जनवरी

- आम बजट में हो सकती है घोषणा
- शेयरधारकों पर लगाया जा सकता है कर
- प्रत्यक्ष कर समिति ने की थी सिफारिश
- निवेशकों की धारणा में होगा सुधार
- कंपनियों के लिए घटेगी प्रभावी कर की दर

निवेश बढ़ाने के लिए अगले आम बजट में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को खत्म किए जाने की संभावना है। इसके बजाय शेयरधारकों पर कर लगाया जा सकता है। सरकार के इस कदम से निवेशकों की धारणा सुधारने में मदद मिलेगी और कंपनियों के लिए कर की प्रभावी दरों में कमी आएगी। सूचीबद्ध कंपनियां शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने से पहले डीडीटी काटती हैं। अधिभार और शिक्षा उपकर के साथ अभी इसकी प्रभावी दर 20.55 फीसदी है। इसके लिए आय कर कानून की धारा 115 (ओ) में संशोधन करना होगा। एक सूत्र ने बताया कि यह कराधान के पुराने तरीके को अपनाने के इरादे से किया जाएगा जहां लाभांश पाने वाले व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। बजट कंपनियों के लिए बार-बार कराधान की समस्या का समाधान करेगा।

सरकार का यह कदम प्रत्यक्ष कर ढांचे में बदलाव के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुकूल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व सदस्य अखिलेश रंजन की अगुआई वाली इस समिति ने डीडीटी को खत्म करने लेकिन दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर (एलटीसीजी) और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बरकरार रखने का सुझाव दिया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के शीतकालीन सत्र में डीडीटी को प्रतिगामी उपाय बताया था। कंपनियां अपने मुनाफे में से लाभांश का भुगतान करती हैं जिस पर पहले ही कर का भुगतान किया जाता है। इस तरह डीडीटी से कंपनियों पर कर का बोझ बढ़ता है। विदेशी शेयरधारकों के लिए भी डीडीटी एक बोझ बन गया है क्योंकि वे सीधे तौर पर इसे नहीं चुकाते हैं। यही कारण है कि उन्हें इसके लिए विदेशी कर क्रेडिट लेना मुश्किल होता है। यह विदेशों में किए गए भुगतान के लिए उनके देश में लगने वाला क्रेडिट है। इससे घरेलू निवेशकों को भी मदद मिलेगी क्योंकि वे आय कर का भुगतान करते समय डीडीटी का क्रेडिट ले सकते हैं। सरकार को हर साल डीडीटी से करीब 60,000 करोड़ रुपये मिलते हैं। अगर सरकार लाभांश के लिए कराधान की पुरानी व्यवस्था अपनाती है तो उसके संग्रह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

प्रशासनिक सुविधा के लिए डीडीटी की व्यवस्था शुरू की गई थी। इसका मकसद लाभांश वितरण करने वाली कंपनी से कर वसूलना था ताकि शेयरधारकों से कर वसूलने के झंझट से बचा जा सके। शेयरधारक को कम कर देना पड़ता है। अगर कोई शेयरधारक एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक लाभांश पाता है तो उससे केवल 10 फीसदी कर लिया जाता है।

वेदांत समूह की कराधान प्रमुख पल्लवी जोशी बाखरू ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में यह कोशिश की जानी चाहिए कि खपत बढ़ाने के लिए शेयरधारकों के हाथ में खर्च करने योग्य अधिक राशि आए और कंपनियों के पास कारोबार के विस्तार और उन्नयन में निवेश के लिए ज्यादा पैसा हो।

बाखरू ने कहा, 'विदेशी शेयरधारकों को अपने देश में डीडीटी के लिए क्रेडिट का दावा करने में संघर्ष करना पड़ता है और अगर उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर कर चुकाना पड़े तो वे कर संधि दरों का दावा कर सकती हैं तो डीडीटी की प्रभावी दर से काफी कम और इस पर आसानी से क्रेडिट लिया जा सकता है। इसलिए डीडीटी को खत्म करने से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।'

अशोक माहेश्वरी ऐंड एलएलपी में मैनेजिंग पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि उद्योग लंबे समय से डीडीटी को हटाने की मांग कर रहा है क्योंकि इसके कारण कंपनियों को तीन बार कर देना पड़ता है। इससे निवेशकों पर भी कर का बोझ बढ़ता है।

एमेजॉन-फ्यूचर के बीच व्यापक साझेदारी

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 19 जनवरी

- एक दूसरे के ब्रांडों का होगा प्रचार
- मार्केटिंग और नवाचार के लिए साझा रणनीति
- अगले दो साल में 1,000 करोड़ रुपये बिक्री का लक्ष्य
- 5 दिन की रिपब्लिक डे सेल 22 जनवरी से

दुनिया की दिग्गज ई-रिटेलर एमेजॉन और किशोर बियाणी की फ्यूचर रिटेल के बीच व्यापक पैमाने पर साझेदारी की योजना है। सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियां एकदूसरे के ब्रांडों का प्रचार करेंगी और मार्केटिंग तथा नवाचार के लिए साझा रणनीति बनाएंगी। उन्होंने अगले दो साल में 1,000 करोड़ रुपये का बिक्री लक्ष्य रखा है।

दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत सबसे पहले पांच दिन की रिपब्लिक डे सेल्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। बिग बाजार में इसे 'सबसे सस्ते दिन' नाम दिया गया है। एक सूत्र ने कहा कि इस फेस्टिवल का आयोजन 22 जनवरी से 26 जनवरी तक किया जाएगा और यह एमेजॉन पर भी उपलब्ध होगी। इस तरह यह ऑनलाइन-ऑफलाइन साझेदारी होगी। फ्यूचर समूह के संस्थापक और फ्यूचर रिटेल के प्रबंध निदेशक बियाणी पिछले कुछ समय से इसका संकेत दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस फेस्टिवल के अनुभवों को बिग बाजार के आगामी सभी सेल्स फेस्टिवल में अपनाया जा सकता है।

इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर के सभी खाद्य और उपभोक्ता सामान भी एमेजॉन पेंट्री पर उपलब्ध होंगे। साथ ही फ्यूचर के फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड एमेजॉन फैशन के कैटालॉग का हिस्सा होंगे।

इस साझेदारी के तहत उत्पादों की दृश्यता और पहुंच बढ़ाने के लिए खाद्य, एफएमसीजी, फैशन और लाइफस्टाइल में फ्यूचर रिटेल के स्टोरों और एमेजॉन प्लेटफॉर्म पर नए ब्रांड उतारे जा सकते हैं। एमेजॉन अपने एमेजॉन नाउ ऐप को प्राइम सदस्यों के बीच जोरशोर से प्रचारित कर रही है। इसके लिए कंपनी ने बिग बाजार को अपना आपूर्ति साझेदार बनाया है। अभी बेंगलूरु, मुंबई और दिल्ली में बिग बाजार के 18 स्टोर से दो घंटे के भीतर आपूर्ति की जा रही है। एमेजॉन नाउ के एमेजॉन इंडिया ऐप के साथ जुड़ने से बिग बाजार के ज्यादा से ज्यादा स्टोरों से प्राइम सदस्यों के लिए आपूर्ति होगी। एक अधिकारी ने कहा, 'यह मॉडल इस तरह काम करेगा कि जैसे ही प्राइम सदस्य ने ऑर्डर दिया, नजदीकी बिग बाजार स्टोर दो घंटे के भीतर आपूर्ति के लिए अलर्ट हो जाएगा।'

इस बारे में बियाणी तुरंत टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। बिग बाजार के कई शहरों में 300 से भी अधिक स्टोर हैं और एमेजॉन के साथ साझेदारी से उसे अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। फ्यूचर और एमेजॉन अपने ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के बीच साझेदारी पर भी विचार कर रही हैं ताकि दोनों की सेवाओं के बीच ज्यादा एकीकरण हो। गूगल पे, पेटीएम और फोनपे जैसे दिग्गज प्रतिद्वंद्वी ई-वॉलेट भारत में जोरशोर से अपना कारोबार फैला रहे हैं। शायद इसी वजह से फ्यूचर और एमेजॉन ने अपने ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म को जोड़ने का फैसला किया है। बियाणी ने पिछले सप्ताह एमेजॉन के 'संभव' कार्यक्रम में कहा था कि फिजिकल स्टोर और डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने-अपने फायदे हैं। अगले कुछ वर्षों में दोनों साथ मिलकर फिजिटल बनाएंगे।

केजरीवाल ने दी मुफ्त बिजली-पानी जारी रहने की गारंटी

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी

- विपक्ष ने चुनाव बाद इन्हें बंद करने का लगाया था आरोप
- छात्रों को भी बस में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का किया वादा
- कुछ वादों की गारंटी केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से सत्ता में आने के बाद अगले पांच साल तक 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 20 हजार लीटर मुफ्त पानी जारी रखने की गांरटी दी। इससे पहले विपक्ष आरोप लगा रहा था कि यह सुविधा 31 मार्च, 2021 तक ही मुफ्त मिलेगी और चुनाव के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने से पहले आप का गारंटी कार्ड जारी किया। जिसमें 10 प्रमुख वादों की गारंटी दी गई है।

गारंटी कार्ड में सबसे पहले सबको 24 घंटे लगातार बिजली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रखने के साथ ही दिल्ली को तारों के जंजाल से राहत दिला भूमिगत केबल बिछाने का वादा किया। दूसरे नंबर पर हर घर को 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी और हर परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना जारी रहने की गारंटी दी है। गारंटी कार्ड में दिल्ली के हर बच्चे का विश्व स्तरीय शिक्षा, सस्ता सुलभ व बेहतरीन इलाज, सबसे बड़ी और सस्ती यातायात व्यवस्था के तहत 11 हजार से अधिक बसें व 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन के साथ ही महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का वादा किया गया है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए प्रदूषण का स्तर तीन गुना तक घटाने के लक्ष्य के साथ ही 2 करोड से ज्यादा पौधे लगाने और यमुना की धारा स्वच्छ व अविरल करने का वादा किया है। केजरीवाल ने कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान की गारंटी दी है।

हालांकि केजरीवाल के गारंटी कार्ड में कुछ वादे ऐसे भी हैं जो दिल्ली सरकार के लिए अकेले पूरे कर पाना आसान नहीं होगा, इनको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग भी जरूरी है। इन वादों में महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली, मेट्रो लाइन का विकास, प्रदूषण में 3 गुना कमी का लक्ष्य आदि शामिल हैं।

नरमी से बेफिक्र वैश्विक वाहन कंपनियां

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 19 जनवरी

सुस्ती से नरम पड़ी बिक्री (फीसदी में)

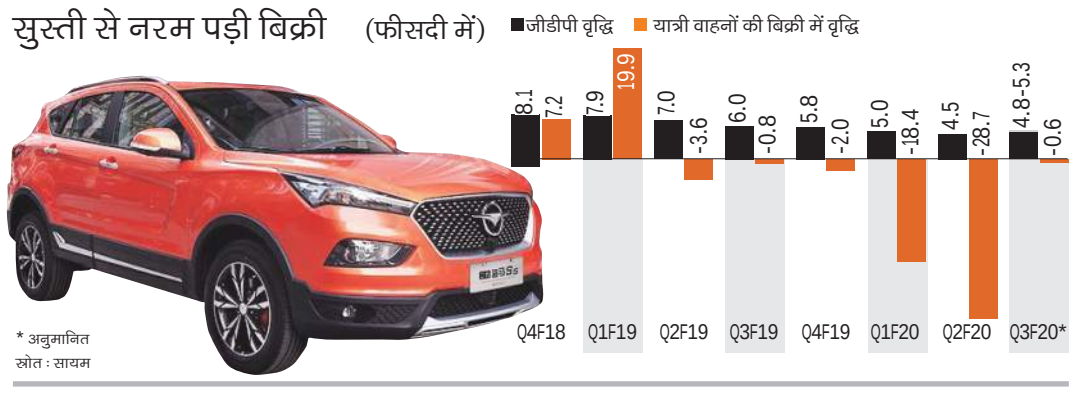

वाहन उद्योग भले ही दो दशक की सबसे गहरी सुस्ती से जूझ रहा हो लेकिन वैश्विक कार विनिर्माताओं के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की योजना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सैक के स्वामित्व वाली एमजी मोटर्स और हुंडई की सहायक इकाई किया मोटर्स ने भातीय बाजार में सफलतापूर्वक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं चीन की कुछ अन्य वाहन कंपनियां जैसे कि ग्रेट वॉल मोटर्स, एफएडब्ल्यू हाइमा ऑटोमोबाइल और शैंगन ऑटोमोबाइल भी भारत में आने की तैयारी कर रही हैं।

इन तीनों कंपनियों ने फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाले ऑटो एक्सपो में शामिल होने की पुष्टि की है। इनके अलावा गीली और चेरी ऑटोबाइल भी भारतीय बाजार में आने की रणनीति बना रही हैं। नए ब्रांड ऐसे समय में बाजार में उतर रहे हैं जब वाहन उद्योग में व्यापक नरमी देखी जा रही है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी सुस्त है। देश में यात्री वाहनों की बिक्री लगातार छह तिमाही से गिरावट आ रही है। इस श्रेणी की सालाना बिक्री 2019 में 20 साल के निचले स्तर पर रही। लेकिन इन चुनौतियों से नए ब्रांड बेफ्रिक नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वाहन उद्योग नियामकीय उत्सर्जन में मानकों, सुरक्षा एवं ईंधन दक्षता को लेकर व्यापक बदलाव से गुजर रहा है। इसके साथ ही सरकार ई-वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है।

आईएचएस मार्किट में सहायक उपाध्यक्ष पुनीत गुप्ता ने कहा, 'यह स्थिति बाजार में आने वाली नई कंपनियों के लिए लाभकारी हैं।' उन्होंने कहा कि मौजूदा फर्मों को नए नियमन के हिसाब से तालमेल करना होगा जबकि नई कंपनियों के साथ ऐसी समस्या नहीं है। पिछले कुछ साल से भारत में आने की योजना बना रहे चीन के विनिर्माता भी सुस्ती वाले बाजार में किया मोटर्स और एमजी मोटर्स के हालिया प्रदर्शन से उत्साहित हैं। किया ऑटो शो में चार नए मॉडल वहीं एमजी मोटर्स द्वारा 14 वाहन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। वाहन विनिर्माताओं का संगठन सायम के अनुसार किया ने पिछले साल जुलाई में सेलटोस को बाजार में उतारा था और दिसंबर तक एसयूवी बाजार में 6.23 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने में सफल रही। एमजी मोटर्स के हेक्टर की प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में 2.20 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है। नई कंपनियों ने मारुति सुजूकी, टाटा मोटर्स, महिंद्र जैसी कंपनियों की हिस्सेदारी में सेंध लगाई है। हाल तक महिंद्रा ऐंड महिंद्रा का एसयूवी में वर्चस्व था लेकिन चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में उसकी हिस्सेदारी घटकर 20.14 फीसदी रह गई। फ्रोस्ट ऐंड सुलिवन में उपाध्यक्ष-मोबिलिटी कौशिक महादेवन ने कहा, 'सही उत्पाद और कीमत ने इन कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की है।'

संक्षेप में

इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश 41 फीसदी घटा

इक्विटी से जुड़ी म्युचुअल फंड योजनाओं में निवेशकों ने 2019 में करीब 75,000 करोड़ रुपये लगाए। यह 2018 की तुलना में 41 फीसदी कम रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव और अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश नीचे आया है। हालांकि , विशेषज्ञों का मानना है कि इक्विटी से जुड़ी म्युचुअल फंड योजनाएं इस साल निवेशकों को आकर्षित कर सकती हैं क्योंकि बाजार के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। एसबीआई म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अश्विनी भाटिया ने कहा, कुछ और समय के लिए बाजार में उथल-पुथल जारी रहने का अनुमान है और हमारा मानना है कि निवेशक इससे फायदा उठाना चाहेंगे और इसका इस्तेमाल धन सृजन में करना चाहेंगे। हमारा मानना है कि इक्विटी फंड समेत म्युचुअल फंड की सभी श्रेणियों में ठीक वृद्धि देखने को मिलेगी। *भाषा*

एफपीआई ने किया 1,288 करोड़ रुपये निवेश

अमेरिका और ईरान के कारण बढ़े भू-राजनीतिक तनाव तथा घरेलू आर्थिक चुनौतियों के बावजूद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जनवरी में अब तक घरेलू पूंजी बाजारों में शुद्ध रूप से 1,288 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस तरह जनवरी में एफपीआई शुद्ध लिवाल बने हुए हैं। नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने एक जनवरी से 17 जनवरी के दौरान शेयरों में 10,200 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि उन्होंने बॉन्ड या ऋण बाजार से 8,912 करोड़ रुपये की निकासी की। इस तरह आलोच्य अवधि में उन्होंने शुद्ध रूप से 1,288 करोड़ रुपये का निवेश किया। ग्रो के सह-संस्थापक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हर्ष जैन ने कहा कि अधिकांश एफपीआई निवेश अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुआ है। *भाषा*

म्युचुअल फंडों की और योजनाओं पर वोडा-आइडिया का जोखिम

रेटिंग एजेंसियों के मूल्यांकन से लगेगा मार्क टु मार्केट नुकसान का झटका

जश कृपलानी
मुंबई, 19 जनवरी

समायोजित सकल राजस्व के बकाए की वजह से वोडाफोन आइडिया पर दिवालिया का जोखिम शुक्रवार को म्युचुअल फंडों की और योजनाओं में फैल गया और रेटिंग एजेंसियों की तरफ से किए गए मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में इस कंपनी में निवेशित योजनाओं के एनएवी में 4 से 10 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया की ऋण प्रतिभूतियों में म्युचुअल फंडों का निवेश 31 दिसंबर 2019 3,389 करोड़ रुपये था, जो 45 योजनाओं के जरिए निवेशित था। यह जानकारी वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों से मिली।

यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड का वोडाफोन की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश योजना की परिसंपत्ति का 17 फीसदी है और उसके एनएवी में 10.42 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। यूटीआई बॉन्ड फंड (8.32 फीसदी निवेश) ने अपने एनएवी पर 4.15 फीसदी मार्क टु मार्केट असर पड़ा।

एक नोट में यूटीआई एमएफ ने कहा, मौजूदा अनिश्चितता और यूनिटधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए यूटीआई एमएमसी ने वोडाफोन आइडिया के एनसीडी की वैल्यू रेटिंग एजेंसियों की तरफ से मुहैया कराए गए मूल्यांकन के मुताबिक करने का फैसला लिया है, जो निचली दो कीमतों पर आधारित होगा और यह 17 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा।

नोट ने कहा, यूटीआई एएमसी भविष्य की प्रगति के आधार पर मूल्यांकन की समीक्षा करेगी और निवेशकों को इससे अवगत कराएगी। यूटीआई एमएफ के दो क्लोज ऐंड फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (30-9 1,266 दिन और 27-2 1,161 दिन) के एनएवी में भी क्रमश: 3.08 फीसदी और 1.7 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। कुल मिलाकर यूटीआई एमएफ ने वोडाफोन आइडिया की ऋण प्रतिभूतियों में 557 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

निप्पॉन इंडिया एमएफ और बिड़ला सन लाइफ एमएफ की योजनाओं पर भी इसका असर पड़ा है। निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड फंड (7.42 फीसदी निवेश) के एनएवी में 3.38 फीसदी की गिरावट आई। निप्पॉन इंडिया एमएफ के 13 एफएमपी ने मार्क टु मार्केट 2 से 4 फीसदी का असर देखा। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया में निप्पॉन इंडिया एमएफ का 243 करोड़ रुपये निवेश है।

आदित्य बिड़ला एमएफ ने वोडाफोन आइडिया में 514 करोड़ रुपये निवेश किया है, लेकिन जिन चार योजनाओं के जरिए इनमें निवेश किया गया है उस पर बहुत असर नहीं दिखा। इसका एमटीएम असर करीब एक फीसदी रहा।

विशेषज्ञों ने कहा, योजनाओं के एनएवी पर असर आगामी दिनों में अलग-अलग दिख सकता है, जो इस पर निर्भर करेगा कि फंड हाउस ने वोडाफोन आइडिया की प्रगति पर क्या कदम उठाया और क्या रेटिंग में और गिरावट आएगी।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने गुरुवार से ही वोडाफोन आइडिया की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को शून्य करने का फैसला लिया है यानी पूरी रकम बट्टे खाते में डालने का फैसला लिया है। 31 दिसंबर 2019 तक फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ का वोडाफोन की ऋण प्रतिभूतियों में 2,074 करोड़ रुपये निवेश था। निवेश को बट्टे खाते में डालने से इनमें 4 से 5 फीसदी की गिरावट आई।

अगर वोडाफोन आइडिया की ऋण सुविधा को मौजूदा बीबीबी से डाउनग्रेड कर दिय जाता है तो यह उसे निवेश श्रेणी से नीचे ला देगा। इससे सभी फंड हाउस को सेबी के नियम के मुताबिक वोडाफोन की ऋण प्रतिभूतियों में अपना निवेश बट्टे खाते में डालना होगा। पिछले साल नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय के सरकार के हक में दिए गए फैसले के बाद केयर रेटिंग्स ने वोडाफोन की लंबी अवधि की बैंक सुविधा और एनसीडी की रेटिंग ए से घटाकर बीबीबी कर दी थी।

वोडाफोन की परेशानी से फंड चिंतित

- वोडाफोन आइडिया की ऋण प्रतिभूतियों में म्युचुअल फंडों का निवेश 31 दिसंबर 2019 को 3,389 करोड़ रुपये था, जो 45 योजनाओं के जरिए निवेशित था
- वोडाफोन आइडिया पर दिवालिया का जोखिम शुक्रवार को म्युचुअल फंडों की दूसरी योजनाओं में फैल गया
- रेटिंग एजेंसियों की तरफ से किए गए मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में इस कंपनी में निवेशित योजनाओं के एनएवी में 4 से 10 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई

पीरामल के राइट्स इश्यू को मिले 8 फीसदी आवेदन

समी मोडक
मुंबई, 19 जनवरी

मंगलवार को बंद होगा राइट्स इश्यू, पूरा आवेदन मिलने का प्रवर्तकों को भरोसा

अजय पीरामल की अगुआई वाली पीरामल एंटरप्राइजेज के 3,650 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को पेशकश के अगले दो दिन में काफी कुछ करना होगा क्योंकि शुक्रवार तक इस पेशकश को 10 फीसदी से कम आवेदन मिले हैं।

बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, राइट्स इश्यू को 22.2 लाख शेयरों के लिए बोली मिली है, जो 2.8 करोड़ शेयरों की पेशकश का महज 8 फीसदी है। राइट्स इश्यू के तहत मौजूदा शेयरधारक मोटे तौर पर मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले छूट पर और शेयर खरीदने के हकदार होते हैं।

यह इश्यू मंगलवार को बंद होगा। ऐसा पाया गया है कि राइट्स इश्यू के लिए ज्यादातर आवेदन आखिरी तारीख पर होता है। अगर इस पेशकश को पूरा आवेदन नहीं मिलता है तो 46.1 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले प्रवर्तकों को इस कमी की भरपाई करनी होगी। कंपनी ने एक ईमेल के जवाब में कहा, हमें राइट्स इश्यू को पूरा आवेदन मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर पूरा आवेदन नहीं मिलता है तो इश्यू की कामयाबी के लिए प्रवर्तकों को इस कमी की भरपाई करनी होगी।

पीरामल एंटरप्राइजेज कर्ज घटाने के लिए रकम जुटा रही है। पिछले वित्त वर्ष के आखिर में कंपनी का कुल कर्ज 56,000 करोड़ रुपये था जबकि कर्ज-इक्विटी अनुपात 2:1। विश्लेषकों ने कहा, एनबीएफसी के लिए कर्ज का स्तर सहज है। रकम जुटाने की हालिया कवायद के साथ कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में और मजबूती की उम्मीद है।

शुक्रवार को पीरामल एंटरप्राइजेज ने हेल्थकेयर एनालिटिक्स बिजनेस डिसिजन रिसोर्सेस ग्रुप (डीआरजी) का विनिवेश अमेरिका में सूचीबद्ध क्लेरिवेट एनालिटिक्स को करने का ऐलान किया था। यह सौदा अगले महीने पूरा होने की उम्मीद है और इससे कंपनी को करीब 6,750 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस घोषणा के बाद कंपनी का शेयर 5.2 फीसदी की उछाल के साथ 1,627 रुपये पर बंद हुआ।

राइट्स इश्यू में 1,300 रुपये के भाव पर निवेशकों को शेयरों की पेशकश की गई है, जो मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले 20 फीसदी छूट पर है।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस शेयर की 12 महीने की लक्षित कीमत 2.022 रुपये है, जो मौजूदा स्तर से 24 फीसदी ज्यादा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, ईस्ट ब्रिज कैपिटल, कनाडा की संस्थागत निवेशक सीडीपीक्यू और अबरदीन इस कंपनी के कुछ अहम सार्वजनिक शेयरधारक हैं। कंपनी ने कहा, राइट्स इश्यू को संस्थागत व खुदरा निवेशकों से अच्छी व मजबूत प्रतिक्रिया मिल रही है। ज्यादातर बड़े संस्थागत निवेशकों ने पहले ही राइट्स इश्यू में भागीदारी की पुष्टि कर दी है।

डीआरजी की बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाने और एनबीएफसी कारोबार को विशाखित करने पर होगा और ये बातें शुक्रवार को कंपनी के चेयरमैन अजय पीरामल ने कही थी।

कंपनी का मानना है कि एनबीएफसी क्षेत्र में संकट मजबूत कंपनियों को काफी मौके उपलब्ध कराएगा।

30 फीसदी ज्यादा फ्रेशर्स को नौकरी देगी टीसीएस

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 19 जनवरी

वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में कुल कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के बावजूद आईटी सेवा दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की योजना आगामी वित्त वर्ष में फ्रेशर्स की बड़ी संख्या नियुक्त करने की है। मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी वित्त वर्ष 2021 में 39,000 फ्रेशर्स की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के मुकाबले 30 फीसदी ज्यादा है।

टीसीएस के कार्यकारी उपाध्यक्ष और वैश्विक प्रमुख (मानव संसाधन) मिलिंद लक्कड़ ने कहा, हमने वित्त वर्ष 2019 में कैंपस से 30,000 लोगों को नियुक्त किया और आगामी वित्त वर्ष में 39,000 लोंगो को जोड़ेंगे। हमने फ्रेशर्स को ऑफर लेटर दे दिया है, जो हमारे टीसीएस नैशनल क्लालिफायर टेस्ट में चुने गए थे।

लगातार पांच तिमाही में शुद्ध कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के बाद मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी के कुल कर्मियों की संख्या दिसंबर तिमाही में 4,063 घटकर 4,46,675 रह गई। तीसरी तिमाही में नौकरी छोड़ने की दर 60 आधार अंक बढ़कर 12.2 फीसदी रही। कंपनी के एचआर प्रमुख ने कहा, हमने फ्रेशर्स को इस साल जल्दी नौकरी दी और इसी वजह से कुल कर्मचारियों की संख्या घटी। वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में फर्म ने शुद्ध आधार पर 22,390 कर्मचारी जोड़े। अन्य समकक्ष कंपनियों के उलट टीसीएस नौकरी छोड़ने की स्वैच्छिक व अस्वैच्छिक दर के अलग-अलग आंकड़े नहीं बताती। टीसीएस एचआर प्रमुख ने कहा कि फ्रेशर्स की नियुक्ति का कर्मचारी पिरामिड पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी नई तकनीक से लैस करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रही है।

बीएस बातचीत

बढ़त की पर्याप्त गुंजाइश, हमें तेजी से बढ़ाने होंगे कदम

तीसरी तिमाही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए सबसे कमजोर तिमाहियों में से एक रही है। इस अवधि में कंपनी के राजस्व की रफ्तार क्रमिक आधार पर न सिर्फ अन्य कंपनियों के मुकाबले सबसे कम रही बल्कि पिछली आठ तिमाहियों में भी सबसे कमजोर रही। हालांकि कंपनी को सुधार का भरोसा है और उसका मानना है कि मौजूदा मंदी व्यापक नहीं है। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी **वी रामकृष्णन** ने **देवाशिष महापात्र** को दिए साक्षात्कार में कहा कि टाटा समूह की कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है। मुख्य अंश...

पिछली दो तिमाही में टीसीएस के राजस्व की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसकी क्या वजह है?

वास्तविकता यह है कि हमने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है। हमें खुद के विश्लेषण से यह पता चला है। दूसरा, कोई बड़ा सौदा नहीं हुआ। ऐसे में जो कुछ हो रहा है वह व्यापक नहीं है। कुछ ऐसे हिस्से व बाजार हैं जहां चीजें अलग नजर आ रही है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संदर्भ में बैकिं ग व वित्तीय सेवाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। बीमा का प्रदर्शन हर बाजार में बेहतर है। अमेरिका में कुछ बड़े बैंकों का बजट कम नहीं हुआ है। लेकिन ये बैंक कम पैसे में ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें परिस्थिति का इष्टतम उपयोग करना होगा और स्वचालन का फायदा उठाना होगा। ब्रिटेन में बीएफएस का प्रदर्शन कई तिमाही से बेहतर रहा है, लेकिन कुछ क्लाइंटों ने तीसरी तिमाही में खर्च घटाया। ऐसे में कुछ बाजार बेहतर कर रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो हमने स्पष्ट तौर पर बाजार हिस्सेदारी का विस्तार किया है।

21 अरब के सालाना राजस्व पर टीसीएस में आधार प्रभाव दिख रहा है। ऐसे बड़े आधार पर क्या हर वित्त वर्ष में दो अंकों में बढ़त की उम्मीद करना सही होगा?

इसके दो पहलू हैं। मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से हमारा नजरिया तकनीक से जुड़ाव रखने वाले कारोबारी मौकों पर तेजी का है। ऐसे में आकार का बहुत मोल नहीं है। बढ़त की पर्याप्त गुंजाइश है क्योंकि तकनीक में इन कारोबार के कायापलट की क्षमता है। प्रशासन व प्रबंधन के लिहाज से हमारी कंपनी के भीतर कई छोटी टीसीएस है। ये ऐसे कारोबार हैं जिनके ऊपर खुद के लाभ-हानि खाते समेत कई जवाबदेही है। इस नजरिये से हमारा कारोबार काफी मॉड्यूलर है। लेकिन हमें ऐसी गुंजाइश पर अन्य के मुकाबले तेजी से कदम बढ़ाना होगा।

25 फीसदी परिचालन मार्जिन पर टीसीएस आईटी सेवा फर्मों में सबसे आगे है। प्रतिस्पर्धा का माहौल में क्या यह टिकाऊ होगा?

अगर आप पिछले 5-6 साल के मार्जिन को देखें तो आप पाएंगे कि यह काफी सुदृढ़ रहा है। हमारे मॉडल की ताकत हमें भरोसा देता है कि यह टिकाऊ है। यह मॉडल तीन चीजों पर आधारित है। पहला, यह तकनीकी स्वीकार्यता पर आधारित है। दूसरा, हमारी क्षमता, जिसके लिए लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही जब हम लंबे समय तक ग्राहकों के साथ काम करते हैं तो यह हमें प्रासंगिक जानकारी देता है।

आरआईएल : आय में मुख्य कारोबार का घटेगा हिस्सा

दिसंबर तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की आय की रफ्तार को उपभोक्ता कारोबार (खुदरा व डिजिटल) काफी सहारा मिला। हालांकि कुल आय का बड़ा हिस्सा उसके मुख्य कारोबार से हासिल हो रहा है, जिसका एबिटा में योगदान करीब 60 फीसदी रहा। हालांकि इसमें तेजी से बदलाव हो सकता है और वित्त वर्ष 2022 के आखिर तक मुख्य कारोबार की हिस्सेदारी घटकर 50 फीसदी रह जाने का अनुमान है। आरआईएल के मुख्य कारोबार तेल, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग का एबिटा में योगदान दिसंबर तिमाही में घटकर 60 फीसदी रह गया। *बीएस*

रिजर्व बैंक ने बढ़ाया स्वर्ण भंडार

वर्ष 2019 में छठे सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा आरबीआई, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए अक्टूबर में 7.5 टन सोना खरीदा जो बढ़कर हुआ 450 अरब डॉलर से ज्यादा

राजेश भयानी
मुंबई, 19 जनवरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए अक्टूबर में 7.5 टन सोना खरीदा है जो अब बढ़कर 450 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। हालांकि विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के अनुसार सोने के रूप में भंडार में यह इजाफा पांच महीने के अंतराल पर किया गया है। परिषद ने केंद्रीय बैंकों के भंडारण को लेकर हाल ही में रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने स्वर्ण खरीद के उन आंकड़ों पर आधारित है जिसकी सूचना उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी थी।

आरबीआई के पास अब 625.2 टन या विदेशी मुद्रा भंडार का 6.6 प्रतिशत सोना है। आरबीआई अब भी केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण खरीद के मामले में पीछे है। लेकिन वर्ष 2019 में पहले 10 महीने के दौरान की गई स्वर्ण खरीद के लिहाज से आरबीआई 25.2 टन खरीद के साथ छठा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की और पोलैंड ने वर्ष 2019 में भारत से ज्यादा खरीद की है।

आरबीआई नवंबर 2015 में जारी किए गए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू की हेजिंग के लिए सोना खरीद रहा है। डब्ल्यूजीसी के अनुसार नवंबर में केंद्रीय बैंकों ने 27.9 टन सोना शामिल करने की सूचना दी थी। एक साल में अब तक इन बैंकों ने संयुक्त रूप से 570.2 टन सोने की खरीद की है जो वर्ष 2018 की अवधि में की गई खरीद (515.2 टन) के मुकाबले 11 प्रतिशत ज्यादा है।

वर्ष 2019 में उजबेकिस्तान और वेनेजुएला ने विक्रेता के रूप में क्रमशः 16.6 और 30.3 टन सोने की बिक्री की है। केंद्रीय बैंकों के अलावा वर्ष 2019 में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदने वाले संस्थागत निवेशक दूसरे सबसे बड़े स्वर्ण खरीदार के रूप में उभरे हैं। हालांकि जौहरियों और निवेश की खुदरा मांग अब भी सबसे बड़ी है, लेकिन वर्ष 2019 में 400 टन के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की खरीद में उछाल आई है।

डब्ल्यूजीसी ने ईटीएफ को लेकर किए गए ताजा विश्लेषण के आंकड़ों में कहा है कि वर्ष 2019 में केंद्रीय बैंक की खरीद के साथ-साथ स्वर्ण समर्थित ईटीएफ का प्रवाह वैश्विक सोने की मांग का एक बड़ा संचालक रहा है। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन फंडों द्वारा की गई खरीद का यह रुख अगले साल भी जारी रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि अधिकांश वैश्विक इक्विटी ने यह साल सर्वकालिक स्तर पर या इसके आस-पास समाप्त किया है, लेकिन सोने में 10 साल में सबसे ज्यादा मजबूती आई है।

डब्ल्यूजीसी ने सोने के दामों में मजबूती का कारण बताते हुए कहा है कि जब ब्याज दरें कम होती [illegible] तो सोना पसंद की जाने [illegible] परिसंपत्ति रहता है। भविष्य [illegible] हुए लगता है कि वर्ष 2[illegible] के भू-राजनीतिक, आर्थिक संचालक [illegible] रह सकते हैं [illegible] व्यापार युद्ध [illegible] निपटा है [illegible] अनुभव [illegible]

वर्ष 2020 में भी जारी रह सकते हैं सोने के भू-राजनीतिक, बाजार और आर्थिक संचालक

स्वर्ण भंडार

- आरबीआई के पास अब 625.2 टन या विदेशी मुद्रा भंडार के 6.6 प्रतिशत के बराबर है सोना
- आरबीआई अब भी अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण खरीद के मामले में है पीछे
- चीन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की और पोलैंड ने वर्ष 2019 में की भारत से ज्यादा खरीद
- केंद्रीय बैंकों ने नवंबर में अपने स्वर्ण भंडार में शामिल किया था 27.9 टन सोना
- एक साल में अब तक इन बैंकों ने संयुक्त रूप से की 570.2 टन सोने की खरीद

बढ़ेगी पॉलिथीन थैली की म[illegible]

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 19 जनवरी

एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री की छह किस्मों पर प्रतिबंध लगाने के तीन महीने बाद सरकार अब पैकिंग के लिए पॉलिथीन की थैलियों और अन्य उत्पादों की न्यूनतम मोटाई 125 माइक्रोन निर्धारित करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की चीजें प्रतिबंधित हैं। अब इस मानक को और कड़ा किया जा रहा है। अगर यह योजना परवान चढ़ती है, तो खाद्य, कृषि, उर्वरक, कपड़े और अन्य चीजों समेत तमाम सामग्रियों की पैकेजिंग लागत में खासा इजाफा हो जाएगा। पैकेजिंग सामग्री की न्यूनतम मोटाई बढ़ने से पैक किए जाने वाले उत्पादों की लागत भी बढ़ जाएगी। इसी वजह से प्लास्टिक विनिर्माताओं ने थैलि[illegible] समेत प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्[illegible] मोटाई इतनी ज्यादा करने के प्र[illegible] लेकर सरकार से कड़ी आप[illegible]

ऑल इंडिया प्लास्टि[illegible] एसोसिएशन (एआई[illegible] आयोजित प्लास्टि[illegible] कार्यक्रम से इ[illegible] अधिकारी ने [illegible] की न्यूनत[illegible] करने [illegible] प्ल[illegible]

भारत में प्लास्टिक की क्षेत्रवा[illegible]

क्षेत्र	उपभोग (प्रतिशत में)
पैकेजिंग	35
भवन और निर्माण	
कपड़ा	
उपभोक्ता-संस्थागत उत्[illegible]	
परिवहन	
इलेक्ट्रिकल/इले[illegible]	
औद्योगिक/[illegible]	
अन्य	

स्रोत : [illegible]

दावोस में जुटेंगे विश्व के शीर्ष नेता व उद्योगपति

भाषा
दावोस, 19 जनवरी

विश्व की अमीर और ताकतवर हस्तियां इस सप्ताह स्विटजरलैंड के रिजॉर्ट शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) सम्मेलन में जुटने वाली हैं। डब्ल्यूईएफ की यह 50वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी से शुरू हो रही है। बैठक 5 दिन चलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, अफगानिस्तान के अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत से कुछ केंद्रीय मंत्रियों, प्रमुख उद्योगपतियों के अलावा फिल्म अभिनेत्री दीपिका पडुकोणे और सद्गुरु के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।

डब्ल्यूईएफ की इस सालाना बैठक में भारत से 100 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इस बार डब्ल्यूईएफ में जुटे दिग्गज सतत और मिलकर चलने वाली दुनिया पर विचार विमर्श करेंगे। दीपिका डब्ल्यूईएफ में मानसिक स्वास्थ्य पर विचार रखेंगी, तो सद्गुरु वार्षिक शिखर बैठक में सुबह के समय चिंतन सत्रों का आयोजन करेंगे। इस बैठक में दुनियाभर से 3,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

मंच की इस सालाना बैठक का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2020 तक होगा। जिनेवा स्थित इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा कि दुनिया के समक्ष मौजूद बड़ी चुनौतियों मसलन आय असमानता और राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह से पैदा हुए सामाजिक भेद से लेकर जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने पर चर्चा होगी।

डब्ल्यूईएफ के संस्थापक एवं कार्यकारी चेयरमैन क्लाउस श्वाब ने कहा कि कंपनियों ने अब साझेदारी वाले पूंजीवाद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है।

दवा फर्मों के लिए नैतिकता निरीक्षकों की तैयारी

सोहिनी दास
मुंबई, 19 जनवरी

भारत की दवा फर्मों की कठित 'अनैतिक' विपणन गतिविधियों पर बहस के बीच इस उद्योग ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए कंपनियों को कड़े नियम के दायरे में लाने की व्यवस्था की मांग की है।

इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अलायंस (आईपीए) की राय है कि विपणन गतिविधियों को नियमित करने के लिए कानून होना चाहिए और इसका अनुपालन न होने पर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। सरकार से चर्चा के लिए एक प्रस्ताव यह है कि 'नैतिकता निरीक्षक' जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बेहतर अनुपालन हो सके।

औषधि विभाग (डीओपी) ने दवा विपणन गतिविधियों की एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) का मसौदा तैयार किया है, जिसका पालन दवा फर्में 2015 से स्वैच्छिक रूप से कर रही हैं। अभी तक इस संहिता को अनिवार्य नहीं बनाया गया है और ऐसा कोई कानून नहीं है कि दवा कंपनियों द्वारा विपणन के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य हो।

दवा उद्योग की मांग

- दवा लॉबी ने स्वैच्छिक विपणन संहिता पर कानून की मांग की
- दवा कारोबारी जल्द ही डीओपी से मुलाकात कर नैतिक विपणन गतिविधि संहिता लागू करने से जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे
- दवा कंपनियों का मानना है कि विज्ञापन क्षेत्र की तरह से दवा उद्योग में स्वनियमन की व्यवस्था व्यावहारिक नहीं

देश की बड़ी दवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आईपीए के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि एसोशिएसन देश की हर दवा फर्म की निगरानी या उन पर नियंत्रण का काम नहीं कर सकता। देश भर में हजारों फर्में हैं। जैन ने कहा, 'डीओपी को एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जिससे संहिता को लागू होने की निगरानी हो सके और इसे अमेरिकी व्यवस्था की तरह ही अनिवार्य बनाया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों (अगर कोई दवा कंपनी इस संहिता का उल्लंघन करने की दोषी पाई जाती है) को दंडित किया जाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया स्पष्ट बनाई जानी चाहिए।'

उन्होंने कहा कि अपील आदि की एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए और अगर कोई कंपनी दोषी पाई जाती है तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आईपीए का मानना है कि यह सब कुछ संहिता तैयार कर किया जाना चाहिए। आईपीए इस सिलसिले में जल्द ही सरकार से बात करेगा। संगठन ने कहा है कि डीओपी को एक व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें अधिकारियों (या इंसपेक्टरों) की व्यवस्था हो और वे संहिता के अनुपालन की निगरानी करें। उद्योग संगठन का मानना है कि अगर डीओपी के सामने शिकायत लाई जाती है तो उसकी जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। बहरहाल यह तभी संभव है जब संहिता को अनिवार्य बनाया जाए और इस सिलसिले में कानून पारित किया जाए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह संभव है कि यूसीपीएमपी को कानूनी जामा पहना दिया जाए और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम में जुर्माने का प्रावधान कर दिया जाए।

पिछले महीने डीओपी ने एक बैठक बुलाई थी और उद्योग से उनकी राय मांगी थी कि इस संहिता में क्या शामिल किया जा सकता है। उद्योग के साथ इस तरह की एक और बैठक एक महीने के भीतर हो सकती है। उद्योग जगत का मानना है कि चिकित्सकों की लगातार शिक्षा की जरूरत है और दवा उद्योग की यहां बहुत अहम भूमिका है। इस संहिता में दवा फर्मों को अनुमति दी जा सकती है कि वे चिकित्सकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक शिक्षा का प्रायोजन करें।

दवा उद्योग के एक सूत्र ने कहा, 'इसके लिए एक उचित प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए और हर दवा कंपनी को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। चिकित्सकों की शिक्षा की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन साथ ही आतिथ्य सत्कार की पेशकश (उदाहरण के लिए उन्हें रिसॉर्ट ले जाने, परिवार के साथ फेमिली ट्रिप का प्रायोजन) की भी व्यवस्था होनी चाहिए।'

एक प्रमुख दवा कंपनी के चेयरमैन का मानना है कि विज्ञापन की तरह दवा क्षेत्र में स्व नियामक निकाय व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका में फिजीशियन पेमेंट्स सनशाइन ऐक्ट (पीपीएसए) है, जिसमें दवा फर्मों को यह खुलासा करना होता है कि उन्होंने हेल्थकेयर पेशेवर को कोई भुगतान किया है। इस तरह की व्यवस्था भारत में भी करने की जरूरत है। ऐसे में अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करता है तो सरकार ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई करे।' उद्योग का कहना है कि कंपनियों को अपने बही खातों में इस तरह के खुलासे करने चाहिए और अगर कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो यह दस्तावेज डीओपी के नियुक्त अधिकारी को जांच के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

प्रमुख योजनाओं और कर रिफंड पर स्पष्टता चाहते हैं निर्यातक

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 19 जनवरी

निर्यातकों का कहना है कि बजट में कर रिफंड सुस्त रहने और प्रमुख प्रोत्साहन योजनाओं को लेकर अनिनिश्चितता की स्थिति साफ करने की जरूरत है। उनका कहना है कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव के साथ ये मसले वृद्धि दर सुस्त होने के लिए जिम्मेदार हैं।

दिसंबर में लगातार पांचवें महीने वाणिज्यिक निर्यात कम हुआ है, क्योंकि प्रसंस्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से प्राप्तियां कम हुई और सभी प्रमुख निर्यात वस्तुओं से विदेशी मुद्रा की कमाई कम रही है। दिसंबर में 1.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 9 महीनों में से 6 महीनों में निर्यात गिरा है।

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा, 'निर्यातकों के 5 महीनों के दावे अभी लंबित हैं, नकदी खत्म हो गई है और नए सौदों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया ठहर गई है।'

पिछले महीने सरकार ने कहा था कि 83,500 से ज्यादा निर्यातकों को पहले ही एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के 1.12 लाख करोड़ रुपये रिफंड का भुगतान किया जा चुका है। सरकार के मुताबिक सिर्फ 3,604 करोड़ रुपये का रिफंड ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के समक्ष लंबित है।

लेकिन फियो का कहना है कि बड़े निर्यातकों का वर्गीकरण जोखिम की श्रेणी में करने से नकदी की समस्या और बढ़ी है क्योंकि उनका जीएसटी और ड्रॉबैक का दावा भी रुक गया है। जोखिम वाले निर्यातक उन्हें माना गया है, जिन्होंने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया है यह संदेह है कि उन्होंने इसके लिए फर्जी रसीद लगाई है।

सराफ ने कहा कि तमाम ऐसे मामले हैं, जिसमें सरकार को किया गया वास्तविक जीएसटी भुगतान आईजीएसटी की तुलना में कम है और वहीं निर्यातकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तमाम सेवाओं पर ज्यादा जीएसटी लगता है।

इस तरह से अगर एक कारोबारी निर्यातक ने अगर कोई वस्तु 5 प्रतिशत दर पर और सेवाएं 18 प्रतिशत की दर पर ली है तो उसे 5 प्रतिशत आईजीएसटी निर्यात के समय देना होता है। वह आईजीएसटी का नकद भुगतान नहीं भी कर सकता है या सिर्फ एक हिस्से का भुगतान कर सकता है। फियो चाहता है कि इस तरह के मसलों का आगामी बजट में समाधान किया जाए।

प्रमुख निर्यात

(आंकड़े अरब डॉलर में	अप्रैल-दिसं ('18-19)	अप्रैल-दिसं ('19-20)	% बदलाव (सालाना)
इंजीनियरिंग के सामान	61.0	59.7	-2.0
पेट्रोलियम उत्पाद	36.6	33.5	-8.2
रत्न एवं आभूषण	29.7	27.8	-6.3
रसायन (कार्बनि क व अकार्बनिक)	16.4	16.9	2.7
दवा	13.9	15.6	12.0
परिधान	11.3	11.4	0.8
टेक्सटाइल के अन्य उत्पाद	12.1	11.1	-8.2
प्लास्टिक	6.5	5.8	-9.5
इंजीनियरिंग के सामान	6.2	8.8	40.0
समुद्र के उत्पाद	5.4	5.4	0.8

स्रोतः वाणिज्य विभाग

सीबीआईसी कुल 6,421 निर्यातकों को जोखिम वाले के निर्यातक के रूप में चिह्नित किया है, जो कुल 1,85,000 निर्यातकों के महज 3.4 प्रतिशत हैं। इनमें 8 स्टार निर्यातक हैं और उनके द्वारा दिए गए पतों पर वे नहीं पाए जाते हैं। स्टार निर्यातक सरकार द्वारा निर्यात में प्रदर्शन के आधार पर चुने जाते हैं और वे कुछ नियत विस्तारित लाभों जैसे स्वघोषणा के आधार परर सीमा शुल्क मंजूरी, कुछ योजनाओं में बैंक गारंटी से छूट पाते हैं। निर्यातकों को यह भी उम्मीद है कि बजट में पुरानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) को लेकर भ्रम दूर किया जाएगा, जिसे सरकार ने बंद कर दिया है। साथ ही प्रतीक्षित रिमिशन आफ ड्यूटीज ऑर टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (आरओडीटीईपी) योजना पर स्थिति साफ होगी। विदेश व्यापार नीति 2015 में 5 प्रोत्साहन योजनाओं को विलय कर मेगा एमईआईएस पेश किया गया था। यह 8,000 से ज्यादा वस्तुओं के वाणिज्यिक निर्यात को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत निर्यातक 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की नियत दरों पर ड्यूटी क्रेडिट पाते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नया आरओडीटीईपी भी इस तरीके पर आधारित है, लेकिन दरों पर फैसला किया जाना अभी बाकी है।

कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा है कि दरों की घोषणा तत्काल की जानी चाहिए क्योंकि निर्यातकों को इसके लिए समय चाहिए होगा, जिससे कि वे नए ऑर्डर को अंतिम रूप दे सकें और नई योजना के तहत आसानी से काम कर सकें। गार्मेंट और मेड अप सेक्टर के लिए सरकार ने एमईआईएस लाभों को पूर्व भाव 7 मार्च 2019 से वापस ले लिया है। जिंस के दाम में उतार चढ़ाव, खासकर कच्चे तेल के अलावा भारत के निर्यात की राह में मुद्रा में बदलाव अहम है। मुद्रा के उतर-चढ़ाव से निर्यात पर असर पड़ा है। रुपये का मूल्य गिरा है। निर्यातकों का कहना है क्हिस नकारात्मकता से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है। जहां रुपये का मूल्य गिरा है, इसका मूल्य ह्रास एक प्रतिशत कम रहा है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 8 प्रतिशत था। इस नकारात्मक माहौल से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है।

'5 साल में बैंक कर्ज दोगुना करने की जरूरत'

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 19 जनवरी

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने आज कहा कि अगर भारत को 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करना है तो बैंकिंग क्रेडिट को मौजूदा स्तर से दोगुना करना होगा।

कुमार ने कहा, 'इस समय भारत के बैंकिंग क्रेडिट का बकाया करीब 99 लाख करोड़ रुपये है और भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले 5 साल में कर्ज कम से कम दोगुना करने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा कि भारत के बैंकों की उद्योग व अन्य क्षेत्रों की इस तरह की बड़ी मात्रा में मांग को पूरा करने की क्षमता है। एसबीआई लखनऊ सर्किल के दो दिन के दौरे पर आए कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि बड़ी परियोजनाएं न होने की वजह से घरेलू अर्थव्यवस्था में कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल अभी भी कम है।

बड़ी अर्थव्यवस्था

- भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार के मुताबिक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए अगले 5 साल में बैंक कर्ज कम से कम दोगुना करने की जरूरत
- इस समय भारत के बैंकिंग का कर्ज करीब 99 लाख करोड़ रुपये

कुमार ने कहा, 'बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और हम उद्योग के कर्ज की हर जरूरतें पूरी करने में सक्षम हैं।' उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजनों की वजह से कर्ज लेने की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो धीरे धीरे गति पकड़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि अभी चल रही सुधार की प्रक्रिया के अपेक्षित परिणाम एक निश्चित समय के बाद आएंगे, न कि बदलाव के चरण के दौरान। उन्होंने कहा, 'बदलाव की एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है और हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, जिसमें उच्च स्तर पर विमर्श प्रक्रिया को बढ़ाना शामिल है।'

उत्तर प्रदेश में कम कर्ज जमा अनुपात (सीडी रेश्यो) के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीडी रेश्यो किसी भी राज्य के औद्योगीकरण के अनुपाती होता है। उन्होंन कहा, 'अगर औद्योगिक वृद्धि दर ज्यादा होगी तो सीडी रेश्यो भी ज्यादा होगा। कहीं कहीं सीडी रेश्यो 100 प्रतिशत से ज्यादा है, वहीं कुछ राज्यों में यह 40 प्रतिशत से कम है।'

इस समय उत्तर प्रदेश का सीडी रेश्यो 52 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत से ऊपर है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को कहना पड़ा है कि रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को स्थिति सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर जोर दे।

कुमार ने भारत के सरकारी बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि यह वक्त की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि विलय की प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से इसका बैंकिंग उद्योग पर अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था में बड़े बैंकों की जरूरत है। गैर निष्पादित संपत्तियों के बारे में उन्होंने कहा कि 2018 में बैंकों का एनपीए शीर्ष पर था, अब स्थिति बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ग्राहक सेवा में सुधार के लिए निरंतर काम कर रहा है।

4 साल में कोयले की कमी दूर करने की पहल

सरकार की अगले तीन से चार साल में देश में कोयले की कमी को दूर करने की योजना है। इसके लिए सरकार ऐसे 100 कोयला ब्लॉक की नीलामी कर सकती है जिनमें कोयले का खोज कार्य पूरा किया जा चुका है। इससे कोयले की कमी के बदले होने वाले आयात को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खनन क्षेत्र में लाए गए अध्यादेश को सबसे बड़े सुधारों में से एक बताते हुए जोशी ने कहा, 'वैकल्पिक आयात (पर रोक) से कोयला की जो भी कमी होगी हम उसकी तीन से चार साल में भरपाई करना चाहते हैं। यह 2023-24 तक हो सकता है। हम कोयला के बदले में होने वाले आयात को रोकना चाहते हैं।' मंत्रिमंडल ने हाल ही में खनिज कानून अध्यादेश 2020 जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। *भाषा*

हवाईअड्डों की सुरक्षा की कवायद को विस्तार

अनीश फडणीस
मुंबई, 19 जनवरी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) हवाईअड्डों पर असुरक्षित ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान बढ़ा रहा है। इसका मकसद अगले 3 महीनों में मानकों के पूरी तरह अनुपालन का लक्ष्य हासिल करना है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, 'शुरुआत में हम 10 प्रमुख हवाईअड्डों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब इस अभियान में जयपुर, भुवनेश्वर, पटना, विशाखापट्टनम और कोयंबटूर को भी शामिल कर लिया गया है।' उन्होंने कहा, 'अनुपालन सुधर रहा है और हमें पिछले 3 महीने के दौरान ग्राउंड हैंडलिंग को लेकर किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है।'

नागरिक उड्डयन नियामक ने पिछले साल अगस्त में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों की ऑडिट की थी, उसके बाद दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा सूची जारी की गई थी। उसके बाद 10 हवाईअड्डों पर जांच की गई, जहां ग्राउंड हैंडलर और घरेलू एयरलाइंस असुरक्षित गतिविधियां करते पाई गई थीं।

सुरक्षा पर जोर

पिछली घटना अक्टूबर में दिल्ली हवाईअड्डे के परिचालन क्षेत्र में सामने आई थी, जब तो वाहन टकरा गए थे।

घरेलू एयरलाइंस को सुरक्षित हैंडलिंग की अनुमति दी गई है, वहीं विदेशी एयरलाइंस एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, भद्र इंटरनैशनल, बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज और सेलेबी एविएशन की सेवाएं लेती हैं। जांच में एयरलाइंस के परिचालन और ग्रांउंड हैंडलिंग कंपनियों को शामिल किया जाता है।

नियामक एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलर्स व अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे तेल विपणन कंपनियों और कैटरिंग कंपनियों के साथ नियमित बैठकें भी कर रहा है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे।

एयरलाइन अधिकारियों ने हवाईअड्डों पर परिचालन संबंधी व्यवधानों व समय से प्रस्थान को लेकर कर्मचारियों के दबाव का भी उल्लेख किया, जिससे चूक होती है।

बहरहाल कुमार ने कहा कि अब सुधार है। जांच के दौरान डीजीसीए के अधिकारियों ने पाया कि जमीन पर मौजूद उपकरण ईंधन भरने वाले वाहनों की राह में व्यवधान पैदा कर रहे हैं और अब इसे खत्म कर दिया गाय है।

जांच के दौरान एक सामान्य अवलोकन पाया गया कि एप्रन पर अनावश्यक वस्तुएं मौजूद थीं। इसके अलावा कंटेनर और बैगेज ट्रॉली असुरक्षित पाई गईं। कुछ मामलों में पाया गया कि ट्रॉली के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कंटेनर खुले थे या अवांछित वस्तुएं सुरक्षा के लिए खतरा थीं और उनसे नुकसान हो सकता था।

अब ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां विमान आने व जाने के पहले जांच कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि एप्रन एरिया में कोई अवांछित वस्तु न हो। डीजीसीए ने यह भी पाया कि एप्रन एरिया में काम करने वाले कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान ज्यादा दृश्यता वाले जैकेट नहीं पहन रखे थे। इस तरह की चूक को अब दुरुस्त कर लिया गया है।

नई रोजगार नीति लाने की तैयारी में सरकार

सोमेश झा
नई दिल्ली, 19 जनवरी

देश में बेरोजगारी की दर ज्यादा होने की चिंता को देखते हुए नई राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) पेश कर सकती है। इसका प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंत्रिपरिषद की बैठक में 4 जनवरी को पेश किया था, जिसका आयोजन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा 5 साल की क्षेत्रवार योजना तैयार करने के लिए किया गया था।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय ने नए सिरे से एनईपी तैयार करने का फैसला किया है। भारत में एक एनईपी एक दशक से ज्यादा समय से चल रही है। इस तरह की पहली नीति 2007 में अंतरमंत्रालयी सलाह के लिए भेजी गई थी।

सरकार ने 2018 में नौकरियों पर नीति दस्तावेज तैयार करने के ळिए 2018 में अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था और नोएडा के वीवी गिरि नैशनल लेबर इंस्टीट्यूट को श्रम मंत्रालय को एक मसौदा सौंपना था। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने कहा, 'बहरहाल श्रम मंत्रालय मसौदा एनईपी से खुश नहीं है।' यह दूसरा मौका होगाा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार रोजगार पर समग्र नीति तैयार करने पर काम कर रही है।

मसौदा एनईपी में सेक्टरवार और व्यापक आर्थिक स्तर पर नीतिगत मसलों के समाधान की बात की गई है। इसमें श्रम कानून से संबंधित नीतिगत कठिनाइयों और सूक्ष्म व लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान का प्रस्ताव है। राजग सरकार के सत्ता में आने पर 2014 में 2 पृष्ठों की एनईपी सार्वजनिक की गई थी और इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। यह मसौदा पहले से ही था, जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार सत्ता में थी और इसमें असंगठित और गैर कृषि क्षेत्रों खासकर निर्माण क्षेत्र में में कौशल पर ध्यान देने की बात थी, जिससे नौकरियों के सृजन को बढ़ावा मिल सके।

बेरोजगारी दर (%)

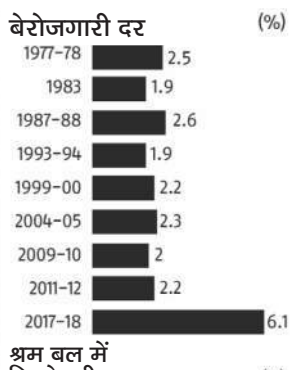

श्रम बल में हिस्सेदारी दर (%)

	2004-05	2011-12	2017-18
पुरुष	84	79.8	75.8
महिला	42.7	31.2	23.3
कुल	63.7	55.9	49.8

नोटः यह 15 साल और ऊपर आयु वर्ग के लिए है, आंकड़े यथास्थिति के हिसाब से

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का श्रम बल सर्वे 2017-18

नए एनईपी दस्तावेदों का आधार उद्योगों, श्रम संगठनों पर राज्य सरकारों से बातचीत के बाद तैयार किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। सितंबर 2019 में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने उद्योग संगठनों व मजदूर संगठनों को पत्र लिखा था, जिसमें रोजगार सृजन, नया प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम और कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर उनकी राय मांगी गई थी।

श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'हमें उद्योग और मजदूर संगठनों से इनपुट मिले हैं। हमने राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय बैठकों में इन मसलों पर राय ली है। जल्द ही सभी हिस्सेदारों के साथ बैठक की जाएगी।'

अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से तमाम कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी की घोषणा करनी पड़ी है। पुनर्गठन की कवायद के तहत ओयो समूह ने करीब 1000 कर्मचारियों को निकालने और वालमार्ट ने 56 कर्मचारियों को हटाने की घोषणा हाल ही में की है। आधिकारिक सांख्यिकी एजेंसी ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 11 साल के न्यूनतम स्तर 5 प्रतिशत पर रहेगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हाल के सालाना सर्वे में कहागया है कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा 6.1 प्रतिशत रही है। कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 2011-12 की तुलना में करीब 8 प्रतिशत घटकर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत रह गई है।

बीएस सूडोकू 3643

		4		3				
	2				7	6		4
	6						1	3
5	3			9				
8			3		6			9
				8			4	2
4	5						7	
1		9	7				6	
				1		4		

परिणाम संख्या 3642

9	1	5	4	7	3	6	8	2
4	7	3	6	2	8	1	9	5
8	6	2	1	5	9	4	7	3
3	2	9	5	4	6	8	1	7
6	8	1	2	3	7	9	5	4
7	5	4	8	9	1	3	2	6
2	9	6	3	1	5	7	4	8
5	3	7	9	8	4	2	6	1
1	4	8	7	6	2	5	3	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम
★★★☆☆

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 287

दूरसंचार क्षेत्र का बचाव

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाइसेंस शुल्क बकाये को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को जोड़ने के उसके आदेश के खिलाफ दूरसंचार कंपनियों की समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के पश्चात सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। करीब 15 दूरसंचार कंपनियों (जिनमें से कई बंद हो गईं या बिक गईं) को 1.47 लाख करोड़ रुपये की राशि चुकानी है। इसमें जुर्माने और ब्याज की राशि शामिल है। दूरसंचार विभाग के पास यह विकल्प है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेकर उद्योग जगत को एजीआर बकाया भुगतान को व्यवस्थित करने को कहे। यदि सरकार या न्यायपालिका से राहत नहीं मिलती है तो दूरसंचार उद्योग को गहन वित्तीय तनाव से बचाने का एकमात्र यही तरीका नजर आता है।

यह सच है कि 1.47 लाख करोड़ रुपये का पूरा भुगतान चालू वित्त वर्ष में सरकार की राजस्व कमी पूरी करने में काफी मददगार साबित होगा। इसके अलावा यदि गैर दूरसंचार कंपनियों का 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का एजीआर बकाया 24 जनवरी तक हासिल हो जाता है तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि वह पहले ही बढ़ते राजकोषीय अंतर से जूझ रही है। परंतु इस मामले में सरकार को अधिकतम राजस्व हासिल करने के विचार से बचना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश के इस अग्रणी क्षेत्र की दिक्कतों को दूर किया जा सके।

फिलहाल दूरसंचार विभाग या किसी भी अन्य सरकारी विभाग को चरणबद्ध भुगतान विकल्प को दूरसंचार उद्योग के लिए राहत मानने के बजाय इसे बचाने का एक उपाय मानना चाहिए। इसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कदमों के दीर्घावधि में क्या परिणाम होंगे। कम से कम एक ऑपरेटर यानी वोडाफोन आइडिया पर यदि यह दबाव बनाया गया कि वह इस सप्ताह के अंत तक 50,000 करोड़ रुपये चुकता करे तो उसका पतन तय है। यानी दुनिया की अव्वल दूरसंचार कंपनियों में से एक ब्रिटेन की वोडाफोन का भारत में सफर समाप्त हो जाएगा। यह कंपनी एक दशक से भी पहले भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाई थी। चूंकि यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में नहीं है इसलिए एक बड़ी कंपनी का यूं पतन होना निवेशकों को प्रभावित करेगा। इसका असर बैंकिंग पर भी पड़ेगा और सरकार के लिए लागत बढ़ेगी।

एक अन्य शीर्ष दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल को 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का एजीआर बकाया चुकाना है। मजबूर करने पर यह कंपनी समय सीमा का ध्यान रख सकती है क्योंकि उसने हाल ही में फंड जुटाया है। परंतु इसका बुरा असर कंपनी की आने वाले दिनों की निवेश संभावनाओं पर अवश्य पड़ेगा। पहला झटका तो उसकी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी की संभावनाओं को ही लगेगा। अतीत में स्पेक्ट्रम की अच्छी खासी कीमतों और रिलायंस जियो के आगमन के बाद आक्रामक प्रतिस्पर्धा के चलते कीमतें कम होने के चलते दूरसंचार उद्योग पहले ही बहुत अधिक कमजोर हो चुका है।

सरकार पिछले 14 वर्ष से भी अधिक समय से दूरसंचार कंपनियों के साथ विभिन्न मंचों पर इस मामले में जूझती रही है और अक्टूबर 2019 में उसे उस समय इस मामले में जीत मिली जब सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित लाइसेंसिंग शुल्क और स्पेक्ट्रम उपभोग शुल्क के आकलन की एजीआर की दूरसंचार विभाग की परिभाषा को मान लिया। बहरहाल, दूरसंचार विभाग को दूरसंचार उद्योग की स्थिति पर ध्यान देने के अलावा दीर्घावधि के राजस्व लक्ष्यों पर भी विचार करना चाहिए। बात यह है कि यदि दूरसंचार क्षेत्र बचता है तो उसका राजस्व सरकार के साथ साझा होता रहेगा। निरंतर राजस्व प्राप्ति के इस स्रोत को नुकसान पहुंचाने से क्या हासिल होगा?

अजय मोहंती

भारतीय 'बनिया' पार्टी की वापसी

मोदी-शाह के अधीन भाजपा कारोबारी मानसिकता की ओर लौट रही है। इससे एक बात रेखांकित हो रही है कि मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकारें भी जोखिम से बच सकती हैं

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने उस वक्तव्य पर तुरंत स्पष्टीकरण दे दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस भारत में निवेश करके उस पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि हर तरह के निवेश का स्वागत है, बशर्ते कि वह देश के नियमों के अनुरूप हो। इस पर बहस मुमकिन नहीं।

इसके साथ ही हमें यह ध्यान रखना होगा कि कारोबार में एकाधिकार पर दृष्टि रखने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बीते दिनों 'अनुचित' कारोबारी व्यवहार के लिए एमेजॉन की खिंचाई की थी। स्वदेशी जागरण मंच और व्यापारी संघों ने इसकी जमकर सराहना की थी। यह कोई दुष्टतापूर्ण षडयंत्र नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीति है। यह केवल इस बात को रेखांकित करता है कि भाजपा बनियावाद की अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर लौट रही है। इसे स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस और वाम ने भाजपा को हिंदू पार्टी कहना शुरू कर दिया। उससे पहले दशकों तक इंदिरा गांधी ऐसा कहने से बचती थीं। इससे पहले इसी स्तंभ में मैंने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी को उद्धृत किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी भाजपा को बनिया पार्टी कहा करती थीं। इन दिनों भाजपा उन्हें सही साबित करते हुए अपनी वणिक मानसिकता में लौटती नजर आ रही है।

स्वदेशी का दर्शन ऐसे ही उत्पन्न होता है। यानी अगर किसी को व्यापार या उद्यमिता से लाभ मिलना है तो अच्छा हो कि वह हमारे लोगों को ही मिले। यदि हम बाहरी लोगों को कारोबार करने भी देते हैं तो बेहतर होगा वह हमारे अहसानमंद हों। इसमें कई मजबूत भावनाओं का मिश्रण हो जाता है: राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद, वाणिज्यवाद और दंभ इसमें शामिल हैं। आखिर आप हैं कौन जो हमारे बाजार में आकर, देसी कारोबारियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करके आशा करते हैं कि मैं आपका धन्यवाद करूं?

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का फैशन सन 1990-91 में शुरू हुआ। उस वक्त शीतयुद्ध समाप्त हुआ था और वही वक्त था जब देश में आर्थिक संकट बढ़ रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट में मधु दंडवते वित्त मंत्री थे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि वह एफडीआई के खिलाफ नहीं हैं लेकिन वे इसकी तलाश में नहीं निकलेंगे। चूंकि वह पुराने समाजवादी थे इसलिए उनके एफडीआई को बेमन से स्वीकार करने को भी खुशी की वजह माना गया लेकिन इससे विदेशी निवेशक आकर्षित नहीं हुए। सन 1991 के सुधार से हालात बदलने लगे लेकिन आंतरिक रुख नहीं बदला। देश पहले ही चार दशक की समाजवादी, संरक्षणवादी, स्वदेशी व्यवस्था से गुजर चुका था जहां निर्यात अच्छा था और आयात बुरा। इसका असर तमाम राजनीतिक फलक पर पड़ा था। आर्थिक दक्षिणपंथ की बात करें तो एक समय ताकतवर रही स्वतंत्र पार्टी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में पूरी तरह ध्वस्त हो गई। उस वक्त तक जन संघ भी वही समाजवादी तराना गुनगुना रहा था और अपने आर्थिक राष्ट्रवाद की चहारदीवारी में कैद था। आधुनिक मुक्त व्यापार की दृष्टि देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के इकलौते सुधारवादी नेता रहे लेकिन उनके पास वक्त कम था।

निष्पक्ष होकर कहें तो पुरानी विचारधाराएं बहुत रूढ़ होती हैं। इन्हें कई वर्ष बीतने पर भी न तो मोड़ा जा सकता है और न ही सीधा किया जा सकता है। कुछ नेता अपने स्तर पर अवश्य बदलाव पैदा कर सकते हैं: कांग्रेस के लिए पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह और भाजपा के लिए वाजपेयी ने ऐसा किया।

बीते साढ़े पांच वर्ष में हमें संरक्षणवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध आदि की तीव्र वापसी देखी है। यह सरकार आयात की तुलना में भारत में बनी पूंजीगत वस्तुओं को 20 फीसदी का लाभ देती है। यह पुराने दौर की वापसी की तरह है।

इसका अर्थ यह हुआ कि एक विदेशी कंपनी अब टुकड़ों में अपनी सामग्री भारत में लाकर यहां उससे माल तैयार करे और अगर वह एक भारतीय अल्पांश भागीदार के साथ मिलकर उसकी बिक्री करे तो आयात की तुलना में कहीं अधिक ऊंची कीमत पर उस माल को बेच सकती है। एक के बाद एक बजट में हमने देखा है कि टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है, क्षेत्रवार संरक्षण बढ़ाया जा रहा है। इस्पात इसका स्पष्ट उदाहरण है। नियामकों समेत तमाम संगठन विदेशी निवेशकों के पीछे हैं। खासतौर पर खुदरा क्षेत्र में। पिछले बजट के बाद और उसे लेकर भाजपा की बहस को देखें तो आयात प्रतिस्थापन की भुला दी गई भावना ने वापसी कर ली।

वैश्विक कारोबारी समुदाय का मोदी शासित भारत से लगाव समाप्त होने की यह भी एक वजह रही। सार्वजनिक रूप से कोई यह बात नहीं स्वीकारेगा। ऐसे कारोबारी तो बिल्कुल नहीं जिन्होंने भारत में निवेश किया हो या जिनके कर्मचारी या अन्य हित भारत में हों। एक मजबूत सरकार से कौन पंगा लेना चाहेगा? वोडाफोन जैसी मजबूत कंपनी के सीईओ ने दुखी होकर भारत छोड़ने की बात कही लेकिन फिर उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी। यह बात अलग है कि नियामकीय कार्रवाइयों और कर झटकों के चलते अरबों की राशि गंवाने तथा व्याप्त अनिश्चितता के बाद उन्हें अभी भी यही करना पड़े। इसके और प्रमाण चाहिए तो देखें कैसे सन 2014 में जेफ बेजोस की पिछली भारत यात्रा के वक्त मोदी और अन्य ने उनका इस्तकबाल किया था और कैसे इस बार उन्हें उपेक्षित किया गया। इस बार भी स्पष्टीकरण सन 1990 के दंडवते जैसा ही है: मैं एफडीआई के खिलाफ नहीं हूं लेकिन...

आप अब भी जानना चाहते हैं कि यह भावना कहां से आ रही है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गत वर्ष दशहरे के अवसर पर दिए भाषण के कुछ हिस्सों को दोबारा सुनिए जिसमें वह अपना आर्थिक सिद्धांत सामने रखते हैं। हम इसे एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं: संरक्षणवादी, विदेशियों से भय, स्वदेशी। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम एफडीआई के खिलाफ नहीं हैं लेकिन केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां हमें उसकी जरूरत है। जब तक यह देश के कारोबारों को नुकसान नहीं पहुंचाता और नियंत्रण भारतीयों के पास रहता है।

मोदी सरकार के कार्यकाल के छठे वर्ष में यह देखना गौरतलब है कि वह नागपुर की आकांक्षाओं का किस कदर ध्यान रख रही है। गाय, अनुच्छेद 370, सीएए, तीन तलाक, पाकिस्तान विरोध आदि सभी मोर्चों पर उसने इसका ध्यान रखा है। वाजपेयी की तरह आरएसएस की उपेक्षा करने के बजाय मोदी सरकार ने उसके साथ तालमेल बिठाने में दो दशक के सुधारों की दिशा उलट दी है। सन 2014 में और उसके बाद 2019 में भारत ने एक मजबूत सरकार और प्रधानमंत्री चुना क्योंकि वह दशकों तक मनमोहन सिंह के अधीन कमजोर सरकार से त्रस्त हो चुका था। यह सरकार कई क्षेत्रों में मजबूत और निर्णायक साबित हुई। आतंकी हमलों के विरोध से लेकर अनुच्छेद 370 और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तक। परंतु आर्थिक मोर्चे पर नहीं। खामीयुक्त जीएसटी और आईबीसी के अलावा कोई बड़ा सुधार नजर नहीं आता।

जरा इस बारे में सोचिए। मनमोहन सिंह जैसी कमजोर सरकार के पास भी यह साहस था कि वह भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौता कर सके। ऐसा करके उसने देश की भूसामरिक स्थिति को बदल दिया था। जबकि मोदी की मजबूत सरकार अमेरिका के साथ एक छोटा व्यापार समझौता तक नहीं कर पा रही। वाजपेयी की कमजोर सरकार ने जीएम बीजों की इजाजत देकर कपास क्रांति लाने में मदद की। मोदी की मजबूत सरकार कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रही। वाजपेयी जिन स्वदेशी वालों की परवाह नहीं करते थे वह उनके लिए फिक्रमंद है।

यहां एक पुरानी दलील सामने आती है: क्या मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकारें अनिवार्य तौर पर बेहतर होती हैं या वे इस उलझन में रहती हैं कि कहीं उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। उनके पास सैद्धांतिक आग्रहों और मजबूरियों का बहाना नहीं होता। वे निरंतर अपना चेहरा बचाने के दबाव में रहती हैं। क्या कमजोर सरकारें अधिक निर्णायक और जोखिम से मुक्त होती हैं क्योंकि उनमें लचीलापन और विनम्रता अधिक होती है? यह उकसाने वाला मुद्दा है। इसे इसीलिए उठाया भी गया है।

शोध के बाद नई सर्पविषरोधी दवा जल्द हो सकती है तैयार

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

बेंगलूरु के साइजीनोम रिसर्च फाउंडेशन के सोमशेखर शेषगिरि की अगुआई में 42 वैज्ञानिकों के दल ने नाग की भारतीय प्रजाति नाजा नाजा के जीनोम का क्रम तैयार किया है। इससे जल्दी ही सर्पविषरोधी दवा के उत्पादन की तकनीक में सुधार आ सकता है। साथ ही इससे ऐसी व्यापक सर्पविषरोधी दवा तैयार की जा सकती है जो विभिन्न तरह के सांपों के विष के खिलाफ कारगर साबित होगी।

सांप के कांटने से भारत में हर साल 46,000 लोगों की मौत हो जाती है। भारत के अलावा पूरी दुनिया में सर्पदंश से सालाना करीब 55,000 लोग मारे जाते हैं। इसी तरह 500,000 लोग सर्पदंश के कारण भारी दर्द, अपंगता और लकवे का शिकार हो जाते हैं और कई लोगों के अंग काटने पड़ते हैं। भारत में सर्पदंश के अधिकांश मामले सांपों की चार प्रजातियों करैत, नाग, सॉ-स्केल्ड वाइपर और रसेल वाइपर से जुड़े होते हैं। हालांकि भारत में विषैले सांपों की 60 से अधिक प्रजातियां हैं।

सांप का जहर विभिन्न तरह के प्रोटीन और पेप्टाइड का मिश्रण होता है जिसका स्राव विषग्रंथि से होता है। सांप के जहर को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक में बांटा जा सकता है। अलग-अलग प्रजाति के सांपों में अलग तरह का विष पाया जाता है। न्यूरो विष से लकवा हो सकता है, साइटो विष रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है जबकि कार्डियो विष से हृदय काम करना बंद कर सकता है। हीमो विष रक्त में ऑक्सीजन के साथ मिलता है जिससे दम घुट सकता है। सर्पविषरोधी दवा का निर्माण मुश्किल, श्रमसाध्य और महंगी प्रक्रिया है और प्रकृति में इसकी मात्रा बहुत कम है।

पहले तो सांप को विष संग्रह जार के ऊपर लटकते मांस को काटने के लिए उकसाया जाता है। इस तरह विष एकत्र किया जाता है। इसके बाद इसका बहुत थोड़ा गैर-विषैला हिस्सा घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है। घोड़ा एंटीबॉडी बनाकर इसके प्रभाव से लड़ता है। इसके बाद घोड़े के रक्त के प्रसंस्करण से सर्पविषरोधी दवा बनाई जाती है। लेकिन इसमें घोड़े की बीमारियों के लिए विशिष्ट दूसरी एंटीबॉडी भी होती हैं। ये न केवल मनुष्य के लिए अप्रासंगिक है बल्कि इससे भयानक एलर्जी भी हो सकती है। कई सर्पविषरोधी दवाओं को मिलाकर एक व्यापक दवा बनाई जा सकती है लेकिन यह सफल या नाकाम प्रयोग हो सकता है, जहां सर्पविषरोधी दवा कुछ खास सांपों के अलावा दूसरे सांपों के काटने पर कारगर नहीं होगी। इसे सबसे पहले 1890 के दशक में इस्तेमाल किया गया था और आज के आधुनिक तरीके भी कमोबेश उसी तरह के हैं। एक बड़ी बाधा यह है कि शोध के लिए पर्याप्त मात्रा में सर्पविष नहीं है।

'नेचर जेनेटिक्स' में प्रकाशित एक नए शोधपत्र में दावा किया गया है कि नाजा नाजा के 38 गुणसूत्रों में से 95 फीसदी जीनोम डिकोड कर लिया गया है। इसमें विषग्रंथि के जीनोम पर खास जोर दिया गया है। शोध दल ने 14 विभिन्न प्रजातियों के नागों के ऊतकों के जीन एक्सप्रेशन डेटा का इस्तेमाल किया।

इसमें कहा गया है कि 12,346 जीन विषग्रंथि से ताल्लुक रखते हैं और इनमें 139 का ताल्लुक 33 विषैली प्रकृति के जीन परिवार से हैं। 139 विषैली जीन में से 19 जीन खासतौर पर विषग्रंथि को दर्शाती हैं और संभवत: ये न्यूनतम मुख्य विष प्रभावकारी प्रोटीन को कूटबद्ध करते हैं। शोधकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी कि कौन सी जीन केवल विषग्रंथि से जुड़ी है।

विष के निर्माण की गुत्थी सुलझाने और दवा बनाने के लिए 33 विषैले परिवारों से ताल्लुक रखने वाली 139 जीनों का समूह और नाग से जुड़े 19 जीन बेहद अहम हैं। यदि इनका संश्लेषण होता है तो सबसे पहले इनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में सिंथेटिक विष बनाने में हो सकता है। फिर इससे सिंथेटिक सर्पविषरोधी दवा बनाया जा सकता है। इस तरह का सिंथेटिक सर्पविषरोधी दवा में एलर्जी पैदा करने वाली घोड़े की एंटीबॉडीज नहीं होगी। इसमें पुन:संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी मददगार साबित हो सकती है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। हर विष के आनुवंशिक क्रम को बढ़ाने के लिए खमीर या ई-कोलाई में डाला जाएगा और इससे बड़ी मात्रा में अलग-अलग विष का उत्पादन होगा। फिर हर विष को मानव ऐंटीबॉडी के साथ मिलाया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा विष कारगर है। फिर विभिन्न प्रकार के विष के मिश्रणों के साथ ऐसा किया जा सकता है।

यह प्रक्रिया बेहद जटिल और श्रमसाध्य है लेकिन इससे बेहतर सर्पविषरोधी दवा बन सकती है। एक बार दूसरे सांपों का जीनोम मैप होने के बाद व्यापक सर्पदंशरोधी दवा बन सकती है। इससे आधुनिक प्रयोगशाला प्रक्रियाएं भी विकसित हो सकती हैं जिससे घोड़े को शामिल किए बिना उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया महंगी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों की संख्या आधा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए नई सर्पदंशरोधी दवा बनाने के लिए पैसों की समस्या नहीं होगी।

शोध के अनुसार, जीनोम को सर्प जीनोम के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आगे आने वाले अध्ययनों में मददगार साबित हो सकता है और इससे विष आधारित औषधि की खोज का रास्ता साफ होगा। विष से जुड़ी विशिष्ट जीनों की पहचान के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें दूसरे सांपों के जीनोम को डिकोड करने में उपयोग किया जा सकता है। सांप के विष के प्रभावों को अभी तक अच्छी तरह नहीं समझा गया है लेकिन विष के सक्रिय तत्त्वों से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। इनसे रक्तचाप काबू में रखने और थक्के को तोड़ने में मदद मिलती है। इस तरह यह शोधपत्र सर्पदंश के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी है। डब्ल्यूएचओ ने सर्पदंश को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी में श्रेणीबद्ध किया है।

कानाफूसी

अफसरशाही दलील

अब जबकि औपचारिक घोषणा की जा चुकी है तो इस बारे में पूरा किस्सा बयान किया जा सकता है कि कैसे अफसरशाही ने ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के गठन की राह रोकने का प्रयास किया। यह भी कि कैसे प्रधानमंत्री ने इसमें दखल दिया। निवर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत को सीडीएस बनना था। वह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सीडीएस को 24 दिसंबर को मंजूरी दी। शीर्ष अफसरशाह प्रधानमंत्री को यह सलाह देते रहे कि वह इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें क्योंकि अफसरशाही में इसे लेकर असहमति है। सेवानिवृत्ति के लिए 65 वर्ष की उम्र और कैबिनेट सचिव के साथ समकक्षता को इसका कारण बताया गया। यह भी कहा गया कि अगर 31 दिसंबर के पहले गजट अधिसूचना जारी नहीं होती तो जनरल रावत सहजता से सेना प्रमुख से सीडीएस नहीं बन पाएंगे। इस पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह चाहते हैं कि अगले दिन यह प्रक्रिया पूरी हो जाए। चाहे जितनी दिक्कत रही हो लेकिन कोई अफसरशाह प्रधानमंत्री की अवज्ञा करने का साहस नहीं जुटा सका।

आपका पक्ष

शांति के लिए इंटरनेट पर पाबंदी भी जरूरी

पिछले साल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इस मामले में हाल में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। अर्थात यह जीने का अधिकार जैसा ही जरूरी है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसलिए शायद उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इंटरनेट पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगाना उचित नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग भी करते हैं। लगभग हर मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिये करती हैं और इस पर कुछ शरारती लोग सोशल मीडिया के जरिये लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जब सरकार किसी संवेदनशील मुद्दे पर फैसला ले तो इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दे जिससे शरारती लोगों और अन्य लोगों को देश के किसी भी जगह अफवाह फैलाने का मौका नहीं मिले। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। अगर सरकार वहां इंटरनेट सेवा पर पाबंदी नहीं लगाती तो शायद शरारती तत्त्व, देश विरोधी ताकतें और नापाक पाकिस्तान के लालच में आने वाले इंटरनेट के जरिये जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करते, साथ ही पूरे देश में भी माहौल खराब करने की कोशिश करते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला उचित था। इंटरनेट पाबंदी से जो देश को आर्थिक नुकसान हो उसकी भरपाई मुश्किल है, लेकिन देश में शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी भी जरूरी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इंटरनेट अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है

जनसंख्या वृद्धि पर लगे लगाम

आज के आधुनिक युग में जनसंख्या का बढ़ना चिंता का विषय है। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती गई तो एक दिन भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो भुखमरी सूचकांक में भी भारत शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो विश्व में चीन जनसंख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर है। उसने अपने देश में जनसंख्या काबू में करने के लिए सख्त रवैया अपनाया है। वहां हम दो हमारे एक की नीति लागू है। भारत में हम दो हमारे दो की नीति अपनानी होगी। अगर यह नीति कारगर नहीं होती है तो फिर प्रकृति अपना रुख अपनाएगी। देश में भुखमरी, सुनामी, बंजर खेत आदि देखने को मिलेंगे। जनसंख्या वृद्धि को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि इससे ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी तथा ज्यादा गुणात्मक वाले लोग बढ़ेंगे। लेकिन अगर विचार किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि न तो देशहित में है और न ही निजी हित में। अत: हमें जनसंख्या सीमित रखने में सहयोग करना चाहिए।

सुप्रिया कुमारी, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

अस्पतालों के रवैये में हो सुधार, स्वास्थ्य बजट बढ़ाए सरकार

व्यापार गोष्ठी

दीपक शर्मा

भ्रष्टाचार के घुन को खत्म कीजिए

बढ़ते भ्रष्टाचार से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी अछूती नहीं हैं। आजादी के इतने वर्ष बाद भी देश के सरकारी अस्पताल आधुनिकता को तरस रहे हैं। भ्रष्टाचार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लकवाग्रस्त कर दिया है। सरकारी अस्पतालों के कुछ डॉक्टर भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। भारत में आबादी और बीमारियां तो बढ़ती गई लेकिन डॉक्टर की संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी पार्टी की सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। डॉक्टरों की कमी का मुख्य कारण मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम होना है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी युवाओं की रुचि बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाइए

विगत वर्षों में गोरखपुर और अब कोटा व गुजरात के सरकारी अस्पतालों में नवजातों की बड़ी संख्या में हुई मौतों ने देश के जनमानस को हिलाकर रख दिया है। इन घटनाओं ने सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था को बेपर्दा कर दिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर भी सरकारी अस्पतालों में नौकरी नहीं करना चाहते हैं। ओपीडी में अत्यधिक मरीज देखने का दबाव भी सरकारी डॉक्टर पर है। जोरशोर से लॉन्च की गई आयुष्मान योजना भी कोई ज्यादा सफल नहीं है। आबादी और बीमारियों के हिसाब से स्वास्थ्य बजट 4 फीसदी होना चाहिए।

अनिल कुमार श्रीवास्तव
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

जागरूकता से सुधरेंगे अस्पताल

सरकारी अस्पतालों में आज आम आदमी को अपना इलाज कराना तो दूर सबसे पहले उसमें अपना दाखिला कराने में भी जोर लगाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में लोगों का सुगमता से इलाज हो इसके लिए सरकार को कागजों में आदेश न करके इस पर धरातल पर काम करना चाहिए। तभी उसके सार्थक परिणाम आएंगे। उदाहरण के तौर पर जहां भी सरकारी अस्पताल हों वहां पर जनप्रतिनिधियों व समाज के जागरूक लोगों की एक निगरानी समिति होनी चाहिए, जो इन अस्पतालों में आने वाले मरीजों की समस्याओं का निराकरण कर सरकार को बदनामी से बचा सकती है। सरकारी अस्पतालों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी प्रकोष्ठ गठित हो। तभी सही निरीक्षण हो सकता है।

दिनेश गुप्ता
पिलखुवा, उत्तर प्रदेश

जिम्मेदार बनें डॉक्टर और अस्पताल

स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर अनेक राज्यों की सरकारों में होड़ मची है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्था की बदहाली व्याप्त है जो समय-समय पर दु:खांतिकाओं का रूप लेकर उजागर होती रहती है। वर्तमान में कोटा के जे जे अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चों की लगातार मौत स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से सुर्खियों में है। बदहाली से निपटने के लिए समस्याओं को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए। आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ की नियुक्ति की जाए। डॉक्टर आजकल निजी प्रैक्टिस को अधिक महत्व देने के साथ दवाओं, उपकरणों में कमीशनबाजी में लिप्त रहते हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

अस्पतालों को मिले पर्याप्त बजट

सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवा, जांच मशीनें, चिकित्सा उपकरण, बेड, डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारी की भारी कमी है जिससे सरकारी अस्पतालों की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की बदहाली दूर करने के लिए सरकार को इन अस्पतालों के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को अपने सालाना बजट में सरकारी अस्पतालों के लिए विशेष फंड का प्रावधान करना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य का बजट काफी कम है। इस बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। अस्पतालों में डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ की भारी कमी है। इसे दूर करने के लिए रिक्त पड़े डॉक्टरों के पदों को भरने के साथ ही अतिरिक्त नई भर्तियां की जानी चाहिए। दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा उपकरणों का भी इंतजाम किया जाना चाहिए।

अनुराग चंदेल
मुंबई, महाराष्ट्र

अस्पतालों का डिजिटलीकरण हो

आयुष्मान जैसी महत्त्वपूर्ण योजना के बावजूद देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर है। अत: जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सरकार को मिलकर अधिक से अधिक देशवासियों को इस महत्त्वपूर्ण योजना के प्रति जागरूक करना होगा ताकि बीमारी में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वे पर्याप्त लाभ उठा सकें। देश की जन स्वास्थ्य सेवाओं को ई-बैंकिंग की तरह डिजिटल रूप से जोड़ना भी लाभकारी होगा। संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी और कानूनी ढांचे को भी मजबूत बनाना होगा। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए एक वेब आधारित नेटवर्क विकसित हो।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

अस्पतालों में गंभीरता का अभाव

मरीज सरकारी अस्पताल में बैठे डॉक्टरों को ईश्वर मानकर स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं। लेकिन कई बार यहां मरीजों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी अस्पतालों में खिलवाड़ होता है। ऐसा नहीं है कि फंड या व्यवस्था के अभाव के चलते सरकारी अस्पतालों की बदहाली सामने आती है अपितु नियमों के उल्लंघन करते कर्मचारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं हैं। यदि इन योजनाओं का संचार शिथिल न हो तो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की कड़ी में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। सरकारी अस्पतालों को व्यवसायिक बनने से रोकना जरूरी है।

दिव्या 'प्रीत' सेठी
नोएडा, उत्तर प्रदेश

स्वास्थ्य को लेकर सरकार हो गंभीर

सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छुपी नहीं हैं। गोरखपुर, कोटा, सूरत के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के मामले दुखदायी हैं। ऐसा भी नहीं हैं कि सरकार को सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा का पता न हो। लेकिन वे इसे सुधारने के प्रति गंभीर नहीं दिख रही हैं। जब कहीं कोटा, गोरखपुर जैसे दर्दनाक होते हैं तो सरकार जागती है और व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कहती हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मामला शांत हो जाता है। वास्तव में अगर सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारनी है तो सरकार को हर समय गंभीरता दिखानी होगी।

रामेंद्र जायसवाल
जयपुर, राजस्थान

अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराएं

विशेषत: निम्न आय वर्ग के लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं देने के लिए ही सरकारी अस्पताल बने हैं। सरकारी अस्पतालों को हर बजट में कोई खास अनुदान न दिया जाना भी सरकारी अस्पतालों के खस्ताहाल होने का बहुत बड़ा कारण है। सरकारी अस्पतालों की हालत अगर वास्तव में बदलना है तो इसे खैराती बनाने की बजाय उचित शुल्क के साथ लोगों को हर आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं देनी चाहिए जैसा निजी अस्पतालों में होता है। बस निजी अस्पतालों की तरह मरीजों का आर्थिक और मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों को एनजीओ बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अस्पतालों को कभी व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि समाज में सस्ती और उत्कृष्ट मेडिकल सुविधा के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिए।

डॉ आंजनेय गुप्त
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

डॉक्टरों के रवैये में जरूरी बदलाव

सरकारी अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वत और बदइंतजामी का बोलबाला है। अस्पताल की अधिकतर जांच मशीनें खराब पड़ी रहती हैं या खराब बताई जाती हैं, ताकि अस्पताल के आसपास चल रहे आधा दर्जन डायग्नोस सेंटरों के मालिकों को फायदा पहुंचा कर उनसे कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय जुटाई जा सके व सरकारी डॉक्टरों की जेब भरती रहे। सरकार यदि वास्तव में सरकारी अस्पतालों के हालात बदलना चाहती है तो डॉक्टरों की सोच बदलनी होगी, उन्हें बताना होगा कि यहां बहुत गरीब मरीज अपनी आर्थिक मजबूरी के चलते आते है। सरकारी अस्पतालों की सभी जांच मशीनों को ठीक कराएं व उनकी लगातार निगरानी की जाए। साथ ही अस्पताल के पास चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच कराई जाए।

कुमारी कबिता
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

संसाधनों का सही उपयोग जरूरी

ये बात तो सही है कि सरकारी अस्पताल पर्याप्त मात्रा में बजट नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन कई जगह बजट होने के बावजूद इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोटा के सरकारी अस्पताल का मामला। इस मामले में पता चला कि अस्पताल के पास करीब 6 करोड़ रुपये का बजट था। फिर भी इस अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की कमी और इनके खराब होने की स्थिति देखी गई। ज्यादातर चिकित्सा उपकरण चालू हालत में नहीं पाए गए। इस वजह से बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी तरह के मामले देश के अन्य सरकारी अस्पतालों में देखे जा सकते हैं।

छवि तिवारी
पटना, बिहार

अस्पताल की व्यवस्था हो चाक चौबंद

सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत को मद्देनजर रखते हुए यह नियम बनाया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी चाहे वह डॉक्टर हो या फिर सफाईकर्मी की अवकाश की अवधि लंबी नहीं हो, जिससे कि मरीज सेवाओं से वंचित न हों। तकनीक से जुड़े कोई भी यंत्र जैसे ऑपरेशन थियेटर, पैथोलॉजी आदि में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की निरंतर जांच एवं सुधार हो। अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ऐसा न हो कि इलाज के लिए आए लोग किसी और ही बीमारी से ग्रसित हो जाएं। किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय औपचारिकताओं में समय बरबाद नहीं किया जाना चाहिए।

डॉ रसिकेश
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

अस्पतालों की रैंकिंग करें

सरकारी अस्पतालों की सेहत वर्तमान में बेहद खराब है। इसके लिए शासन-प्रशासन के साथ-साथ आम लोग और आंशिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी चरित्र भी जिम्मेदार है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली को दूर करने के लिए अस्पतालों की मूलभूत अवसंरचनाओं के साथ डॉक्टरों की कमी को भी दूर किया जाना चाहिए। डॉक्टरों को अपने कर्तव्यों को नैतिक जिम्मेदारी मानकर निजी अस्पतालों में सेवाएं देना बंद कर देना चाहिए और सरकार को भी इन्हें पर्याप्त मात्रा में वेतन, भत्ते और सुविधाएं देनी चाहिए जिससे ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जा सके। स्वच्छता को विशेष ध्यान में रखकर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। अस्पतालों को क्षेत्रीय आधार पर रैंक दी जानी चाहिए जिससे उनके मध्य प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा।

सचिन यादव
अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

सरकारी अस्पतालों की निगरानी हो

सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार, लापरवाही के मामले भी देखे जा रहे हैं जिससे सरकारी अस्पताल बदहाल होते जा रहे हैं। दवा, चिकित्सा उपकरण, जांच मशीन की खरीद से लेकर अस्पताल निर्माण में घोटाले हो रहे हैं। इससे इन अस्पतालों को दिए बजट में जरूरी संसाधन मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर भी इलाज करने में लापरवाही बरत रहे हैं वे अस्पताल में मरीज देखने के बजाय अपने निजी क्लीनिकों पर मरीजों को देखने को तरजीह देते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद से लेकर इलाज की निगरानी करने की सख्त जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार न हो सके। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर भी सरकारी अस्पतालों की बदहाली दूर की जा सकती है। सरकारी अस्पतालों में अधिक से अधिक पलंग की व्यवस्था करने की जरूरत है। स

रंजीत प्रसाद
भोपाल, मध्य प्रदेश

बकौल विश्लेषक

बदले गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार, आधुनिक तकनीकों का हो इस्तेमाल

देश की बेहतर आर्थिक प्रगति के लिए स्वस्थ मानव श्रम बल का होना नितांत आवश्यक है और इसमें सरकारी अस्पताल अहम भूमिका निभाते हैं। देश की अधिकांश आबादी आज भी अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। ऐसे में बदहाल व्यवस्था के चलते यहां हो रही मासूम बच्चों की मौत इस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है और बेहतरी के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करती है। सरकारी अस्पतालों में इस तरह की घटनाओं के पीछे कई कारण होते हैं। जैसे, दवाइयों की अनुप्लब्धता, देखभाल की कमी, लालफीताशाही, अनुचित रखरखाव, मरीज के लिए जरूरी उपचार में देरी आदि। छोटे बच्चों की मृत्यु के मामलों में चिकित्सीय कारक भी अहम होते हैं, जिनमें जन्म पूर्व की जटिलताएं (18 प्रतिशत), निमोनिया (18 प्रतिशत), शरीर संबंधी जटिलताएं (12 प्रतिशत), हैजा (8 प्रतिशत), मलेरिया (5 प्रतिशत) और कुपोषण आदि। शिशु के जन्म लेने के तत्काल बाद स्तनपान, प्रसव एवं प्रसव के बाद उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, आवश्यक पोषण, स्वच्छता तथा टीकाकरण व्यवस्था को दुरुस्त करके करीब दो-तिहाई बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। कई बार अस्पताल अधिक संख्या में मरीजों के आने, स्टाफ की कमी, जरूरी मशीनों का न होना आदि कई तरह के तर्क देते हैं लेकिन यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कुछ सरकारी अस्पतालों में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार देखा जाता है और वहां आपातकाल के लिए जरूरी उपकरणों तथा दवाइयों की भी कमी होती है। इस पूरी प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। सरकारी अस्पतालों को आपनी नीतियां, प्रक्रियाएं बदलनी होंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सके। सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणाएं की हैं और उनकी उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में आधुनिक तकनीकों की व्यवस्था भी की जाए और गरीब मरीजों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

बातचीत: **वीरेश्वर तोमर**

डॉ. जी. डी. मोगली
अध्यक्ष, हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया

स्वास्थ्य बजट बढ़े, अस्पतालों की जिम्मेदारी तय हो

देश की अधिकांश स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं और इन अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय इसे निजी क्षेत्र को सौंपने की वकालत करने वालों की मंशा इस जनकल्याणकारी क्षेत्र को उद्योग बनाने की रही है। हाल ही में कोटा व राजकोट में सैकड़ों बच्चों की मृत्यु, गोरखपुर में जापानी बुखार और मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मौत होने का कारण अलग-अलग है। सरकार ने इन मौतों का कारण भी ढूंढ लिया है। पर उपाय नहीं करने के कारण और मौतें नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सत्ताधारी दल इन मौतों को प्राकृतिक मौतें बता रहे हैं। बीमा आधारित आयुष्मान भारत योजना इसलिए लाई गई क्योंकि केंद्र सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि सरकारी स्वास्थ सेवा को मजबूत नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के आधार जिला अस्पतालों को यदि मजबूत नहीं किया गया तो संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा हाशिए पर चली जाएगी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, चिकित्सा उपकरण, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही गवर्नेंस को मजबूत करना होगा। केरल की विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य योजना, तमिलनाडु के दवाओं की उपलब्धता का मॉडल, दिल्ली का मोहल्ला क्लीनिक और मध्यप्रदेश का संजीवनी क्लिनिक जैसे मॉडल शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य अपनी जिम्मेदारी समझें और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देकर नए प्रयोग करें। अंतर विभागीय समन्वय मजबूत कर हितधारकों के सहभाग से नीचे से लेकर ऊपर तक स्वास्थ्य योजना बनाई जाए। स्वास्थ्य बजट बढ़ाने के साथ ही इसके खर्च की निगरानी हो। यह भी सुनिश्चित हो कि मौजूद चिकित्सा उपकरण चालू हालत में रहें और इनकी कमी को दूर किया जाए। हितधारकों की जिम्मेदारी तय हो तभी जन स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों में सुधार होगा और सरकारी अस्पतालों में नागरिकों को सस्ती व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने भी बने।

बातचीत: **रामवीर सिंह गुर्जर**

अमूल्य निधि
राष्ट्रीय सह-संयोजक, जन स्वास्थ्य अभियान

पुरस्कृत पत्र

स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव की दरकार

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन व सक्षम स्वास्थ्य नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दरकार है। अवसंरचनात्मक सुधार के तहत भवन के साथ ही अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरणों की समुचित आपूर्ति हो। चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों के रिक्त पदों को तुरंत भरें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि संक्रमण की आशंका को शून्य किया जा सके। निगरानी हेतु स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की स्थापना की जाए, जो सरकारी अस्पतालों में अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सकों की नियुक्ति व सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखे। हेल्थकेयर एक्सेस टास्क फोर्स का गठन हो जो जनता तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करे। मोबाइल क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत हो। स्वास्थ्य बजट 4 फीसदी किया जाए।

1

निखिल आर्य
सीकर, राजस्थान

पुरस्कार राशि 500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

डॉ राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

मामूली शुल्क लेकर जिम्मेदारी करें तय

सरकारी अस्पतालों की हालत काफी बदतर है। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना में भी अगर हम कुछ अस्पतालों का उदाहरण हटा दें तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। सरकारी अस्पतालों में भी इलाज अच्छे से हो यह सुनिश्चित करने के लिए मरीजों से मामूली शुल्क लिया जाना चाहिए क्योंकि कई बार फंड की कमी से उचित रख रखाव नहीं हो पाता। चिकित्सकों को भी मानवीय आधार पर मरीजों का इलाज करना चाहिए। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का व्यवहार चिड़चिड़ा होता है जिससे मरीजों में एक भय भी होता है जिसे सामंजस्यपूर्ण बनाने की जरूरत है। वृद्ध, दिव्यांग, महिलाओं तथा गरीबों को प्राथमिकता में वरीयता मिलनी चाहिए। अस्पताल में घर जैसा माहौल होना चाहिए।

उद्देश्य
पटना, बिहार

कायम है बदइंतजामी का सिलसिला

सरकारें बदलने के बाद भी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार आता नहीं दिख रहा है। मरीजों के बेड के नीचे आवारा कुत्ते, चारों तरफ गंदगी का अंबार और बिस्तरों पर गंदी चादरें अब सरकारी अस्पताल की यही पहचान बन गई है। गरीबों को सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा का दावा करने वाली सरकारों के लिए ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। सरकार को अपने बजट में से स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता है। डॉक्टरों से पहले संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर भी अधिक बहाल किए जाएं जिससे किसी एक डॉक्टर पर ज्यादा बोझ न पड़े। आम नागरिकों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि वे अस्पताल में गंदगी न फैलाएं। इस तरह कुछ हद तक अस्पतालों की बदहाली कम हो सकती हैं।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

डॉक्टर व कर्मचारी के खाली पद भरे जाएं

अमूमन देश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं क्योंकि वहां पर सरकार ने न तो पूरे चिकित्सकों को पदस्थ किया है और न ही उचित मात्रा में दवाइयों का ही इंतजाम किया है। नतीजतन आए दिन मरीजों और बच्चों की असमय मौतें होती हैं और परिजनों के गुस्से की परिणति चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार के रूप में सामने आती है। अत: सरकार को युद्धस्तर पर एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू कर इस बदहाली को दूर करना चाहिए। चिकित्सकों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े पद त्वरित गति से भरे जाने चाहिए। साथ ही समय-समय पर बिना सूचित किए निरीक्षण, स्टॉक में रखी दवाइयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

सूर्यभानु बांधे
रायपुर, छत्तीसगढ़

सरकारें करें स्वास्थ्य बजट में इजाफा

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सबसे प्रमुख चुनौती है आबादी के अनुपात में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं, आधारभूत संरचना, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं की भारी कमी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.4 फीसदी ही चिकित्सा सेवा में खर्च किया जाता है। इसे बढ़ाने की काफी जरूरत है तभी आबादी के अनुपात में डॉक्टर, अस्पताल एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निजी चिकित्सा उद्योग सिर्फ चुनिंदा शहरों तक सीमित न रहें बल्कि इनका विस्तार छोटे एवं पिछड़े शहरों में भी हो। निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी रकम न वसूल सकें इसके लिए भी समुचित तंत्र की व्यवस्था की जाए।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -
आपकी राय में कैसा हो आम बजट ?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

ऑनलाइन पर सीसीआई का बढ़ता शिकंजा

सीसीआई के बदले रुख का ई-टेलर के लिए क्या है मायने, बता रही हैं रुचिका चित्रवंशी...

छोटे खुदरा विक्रेताओं ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और एमेजॉन पर एक्सक्लूसिव डील और भारी छूट के साथ उत्पादों की बिक्री करने का आरोप लगाया है

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) देश के ऑनलाइन शॉपिंग जगत में मजा किरकिरा कर सकता है। दो प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइट- एमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव डील और उत्पादों पर भारी छूट अब सीसीआई की जांच के दायरे में है। इसे आगे चलकर ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति सीसीआई के रुख में सख्ती का संकेत माना जा रहा है।

ई-कॉमर्स क्षेत्र की इन दोनों प्रमुख कंपनियों की बाजार गतिविधियों की सीसीआई द्वारा की जा रही पहली औपचारिक जांच है। हालांकि सीसीआई के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने दावा किया है कि दोनों कंपनियां पहले भी प्रतिस्पर्धा आयोग में उलझ चुकी हैं। प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान बदलाव केवल इतना हुआ है कि सीसीआई अब ई-कॉमर्स को खुदरा बिक्री का एक अन्य माध्यम के तौर पर देख रहा है। आयोग खुदरा बाजार को दो श्रेणियों- ऑनलाइन और ऑफलाइन- में बांटकर उन पर अलग से नजर रख रहा है।

मौजूदा जांच का आदेश स्मार्टफोन एवं संबंधित ऐक्सेसरीज के छोटे व्यापारियों के संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत पर दिया गया था। आयोग के पास यह शिकायत प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 3 (1) और (4) के तहत दी गई है। इसके तहत उत्पादों के एक्सक्लूसिव लॉन्च के अलावा कुछ विक्रेताओं को तरजीह दिए जाने और छूट संबंधी गतिविधियों के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव पड़ने का मुद्दा उठाया गया है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारी छूट और बेहद सस्ती कीमत प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन तभी माना जा सकता है जब कोई प्रमुख कंपनी ऐसा करेगी। कानून फर्म लूथरा ऐंड लूथरा के पार्टनर अबदुल्ला हुसैन ने कहा, 'सीसीआई का आदेश किसी बाजार में फ्लिपकार्ट अथवा एमेजॉन के वर्चस्व की जांच नहीं करता है।' हालांकि आयोग ने बाजार में दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों के संयुक्त वर्चस्व की शिकायत को खारिज कर दिया है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि एमेजॉन-फ्लिपकार्ट के मामले में प्रतिस्पर्धा आयोग दोनों प्लेटफॉर्म की बाजार स्थिति पर गौर कर रहा है जबकि स्मार्टफोन विनिर्माताओं की बाजार स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। ट्राईलीगल की पार्टनर एवं राष्ट्रीय प्रमुख (प्रतिस्पर्धा कानून) निशा कौर ओबेरॉय ने कहा, 'यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सीसीआई प्रासंगिक बाजार को किस तरह परिभाषित करता है। ऐसा लगता है कि वह बाजार को दो हिस्सों- ऑनलाइन और ऑफलाइन- में बांटकर देख रहा है।'

नवंबर 2018 में ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ इसी तरह की शिकायत की थी जिसे प्रतिस्पर्धा आयोग ने खारिज कर दिया था जिससे पता चला था कि भारत में मार्केटप्लेस आधारित ई-कॉमर्स मॉडल खुदरा वितरण के एक हिस्से तौर पर उभर रहा है जो काफी हद तक तकनीक से संचालित है। आयोग ने 2018 के अपने आदेश में कहा था, 'वृद्धि की संभावनाओं के साथ-साथ कुशलता एवं इस बाजारों से ग्राहकों के संभावित फायदे को देखते हुए आयोग का मानना है कि इस प्रकार के बाजारों में कोई भी दखल देने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि कोई नवाचार न प्रभावित हो।'

आयोग ने 2015 में इन दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ दायर पहली शिकायत को इस आधार पर बंद कर दिया था कि किसी विनिर्माता और ई-पोर्टल के बीच बिक्री संबंधी विशेष व्यवस्था से बाजार में प्रतिस्पर्धा पर शायद ही कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, विशेषतौर पर मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे अधिकतर उत्पाद एकाधिकार अथवा वर्चस्व के दायरे में नहीं थे।

तो क्या पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान बदलाव केवल इतना दिख रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपना रुख बदल लिया है?

ओबेरॉय के अनुसार, बाजार की परिभाषा में बदलाव के लिए आयोग की दलील में डिजिटल बाजार के उभार की रफ्तार भी शामिल है, खासकर ऑनलाइन यात्रा बाजार के संदर्भ में। ओबेरॉय ने कहा, 'डिजिटल बाजार के उभार की रफ्तार पारंपरिक बाजार के मुकाबले काफी तेज है और इसलिए उसका आकलन करने में मौजूदा बाजार की वास्तविकताओं एवं प्रतिस्पर्धा संबंधी पहलुओं पर गौर करना जरूरी है।'

ई-कॉमर्स बाजार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का ताजा अध्ययन एमेजॉन-फ्लिपकार्ट की जांच के आदेश का लगभग पूर्वगामी है और उससे आयोग के नजरिये में हुए बदलाव का भी पता चलता है। आयोग ने अपने निष्कर्ष को स्व-विनियमन कहा है और उसमें उन्हीं समस्याओं का उल्लेख किया गया है जिनकी जांच ताजा शिकायत के तहत फिलहाल चल रही है। प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ विनोद ढल ने कहा, 'सीसीआई का यह आदेश अनुचित नहीं है। उसने नई प्रौद्योगिकी के लिए सम्मान दिखाया है और कहा है कि इन कंपनियों को ग्राहकों को फायदा देना चाहिए। ई-कॉमर्स पर यह अध्ययन इस क्षेत्र की बेहतर समझ के लिए किया गया है और उसमें इन समस्याओं को उठाया गया है।'

वैश्विक स्तर पर भी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई में तेजी दिख रही है। हुसैन ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर कार्रवाई के लिए मांग उठा रही है क्योंकि गूगल, एमेजॉन, फेसबुक और ऐपल जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों को उन्हीं मुद्दों के लिए अमेरिका और यूरोप में प्रतिस्पर्धा संबंधी जांच का सामना करना पड़ रहा है जिनका उल्लेख सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में की है।'

विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने संगठन में काफी बदलाव किया है। सीसीआई के नए चेयरपर्सन ने नवंबर 2018 में अपना पदभार ग्रहण किया और उसके तुरंत बाद दो सदस्यों को नियुक्त किया गया।

हाल में ऑनलाइन यात्रा पोर्टल मेकमाईट्रिप को भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच का सामना करना पड़ा था। अब तक केवल ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म ही सीसीआई की जांच के दायरे से बाहर निकल पाए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही अन्य ऑनलाइन क्षेत्र की अन्य प्रमुख कंपनियों को भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सख्त रुख का सामना करना पड़ सकता है।

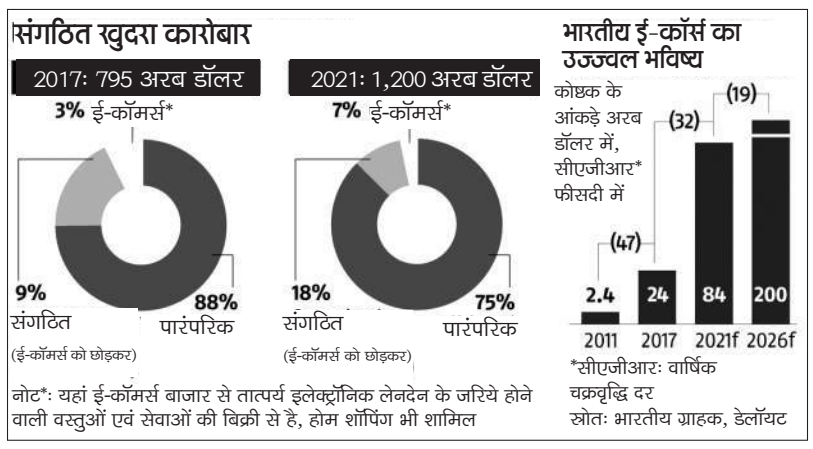

नोट*: यहां ई-कॉमर्स बाजार से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के जरिये होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से है, होम शॉपिंग भी शामिल

आयोग का नजरिया

2015
एमेजॉन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ पहले मामले को बंद किया

2018
फ्लिपकार्ट के खिलाफ शिकायत को खारिज किया

2020
वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग के आरोप की जांच का निर्णय लिया

जांच का दायरा

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन के एक्सक्लूसिव लॉन्च
- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर तरजीही विक्रेताओं को मिलने वाले फायदे
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निजी लेबल के प्रमोशन को प्राथमिकता
- ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश

ये 10 छोटे और मझोले शेयर हैं आकर्षक दांव

राम प्रसाद साहू, हंसिनी कार्तिक और श्रीपाद ऑटे

पिछले दो वर्षों से प्रमुख सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन करने के बाद निफ्टी मिडकैप ने पिछले सप्ताह सात महीने के ऊंचे स्तर को छुआ। निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक में भी तेजी दिखी है और कैलेंडर वर्ष 2019 के अंत में गिरावट से जूझने के बाद इसमें 10 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है। ताजा तेजी से पहले, लार्ज-कैप की तुलना में मिड-कैप के मूल्यांकन में कमी दर्ज की गई थी। अब कम उम्मीदों के बीच सुधरते रिस्क रिवार्ड से इसमें बदलाव आने की संभावना है। वैश्विक नकदी की स्थिति और मजबूत कोष प्रवाह बाजार के लिए अनुकूल है और इस साल आर्थिक सुधार से भी स्मॉल-कैप और मिड-कैप क्षेत्र के शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। एडलवाइस रिसर्च के विश्लेषकों को मिड-कैप का प्रदर्शन उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में शानदार रहने की संभावा है। हालांकि वे निवेशकों को उन कुछ खास शेयरों का चयन करने की सलाह दे रहे हैं जो उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं।

यहां ब्रोकरों के सुझावों के आधार पर उन 10 शेयरों की सूची तैयार की गई है जो राजस्व परिदृश्य, मुनाफा वृद्धि, कर्ज की स्थिति और आकर्षक मूल्यांकन के आधार पर अगले साल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सूची में शामिल शेयरों में अगले साल के दौरान आय और प्रतिफल में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।

इंडियन होटल्स

मौजूदा भाव (रु.)	145.3
कीमत लक्ष्य (रु.)	195.3
तेजी (%)	34.4
पीई वर्ष 2021ई (एक्स)	34.4

- पूरे भारत और विदेश में 18,000 कमरों के साथ सबसे बड़े होटल परिचालन वाली कंपनियों में शुमार है
- कम जीएसटी और अनुकूल मांग-आपूर्ति अंतर की लाभार्थी को प्राप्तियां और राजस्व सुधारने में मदद मिल सकती है
- 5,000 से अधिक कमरों की संभावना, ज्यादातर प्रबंधन अनुबंधों से शामिल होंगे
- लागत नियंत्रण पहल से कंपनी के परिचालन लाभ और मार्जिन में तेजी आ सकती है
- ऐसेट लाइट मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना कर्ज और नकदी प्रवाह के नजरिये से भी सकारात्मक है

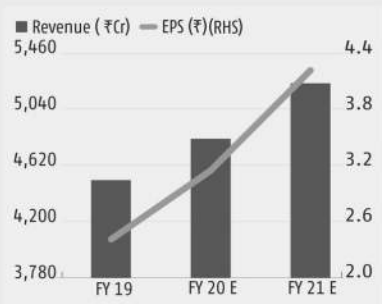

डालमिया भारत

मौजूदा भाव (रु.)	866.0
कीमत लक्ष्य (रु.)	1127.3
तेजी (%)	30.2
पीई वर्ष 2021ई (एक्स)	30.4

- सालाना 1.57 करोड़ टन की क्षमता वृद्धि में 80 प्रतिशत से ज्यादा नए संयंत्रों से जुड़ी क्षमता शामिल है
- 2020 में ज्यादा क्लिंकर इस्तेमाल की उम्मीद से कीमत वृद्धि के साथ परिचालन लाभ में सुधार आने की संभावना है
- प्रबंधन का मानना है कि फंसी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण परिचालन के पहले साल से परिचालन मुनाफा मार्जिन में योगदान देगा
- मुक्त नकदी प्रवाह में संभावित सुधार से कर्ज बोझ घटाने में मदद मिलेगी, शुद्ध कर्ज-पूंजी अनुपात मार्च 2019 में 0.5 गुना पर दर्ज किया गया

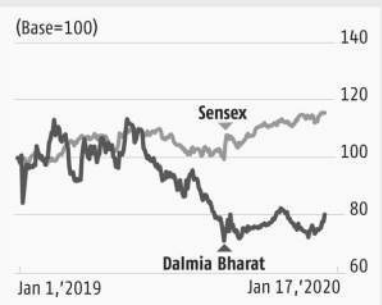

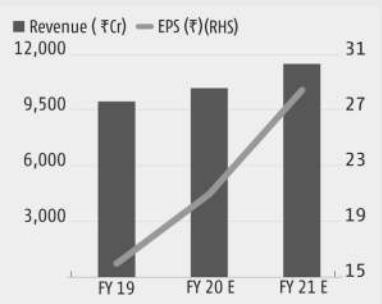

इंजीनियर्स इंडिया

मौजूदा भाव (रु.)	101.8
कीमत लक्ष्य (रु.)	133.9
तेजी (%)	31.6
पीई वर्ष 2021ई (एक्स)	12.0

- हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में कंपनी की बाजार हैसियत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह कंसल्टेंसी और टर्नकी सॉल्युशन मुहैया कराती है
- डीजल कीमतों के विनियमन के बाद, तेल विपणन कंपनियों की मजबूत नकदी प्रवाह स्थिति,
- बीएस-6 अनुकूल इकाइयों के उन्नयन की जरूरत, और अतिरिक्त क्षमताएं जोड़ना इंजीनियर्स इंडिया के लिए अच्छा संकेत है
- जहां ऑर्डर प्रवाह बाद में कमजोर पड़ा है, वहीं 10,700 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक के साथ कंपनी की चार वर्षों के लिए राजस्व संभावना मजबूत हुई है

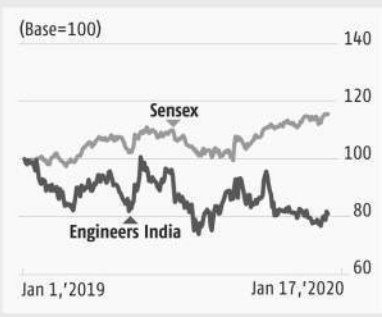

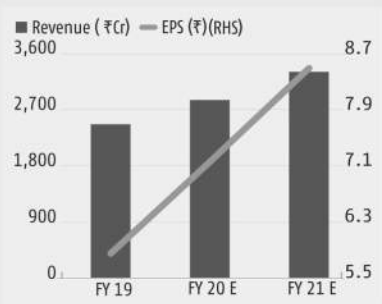

अरविंदो फार्मा

मौजूदा भाव (रु.)	486.3
कीमत लक्ष्य (रु.)	628.8
तेजी (%)	29.3
पीई 2021ई (एक्स)	9.0

- सैंडोज अधिग्रहण के पूरा होने और इससे प्राप्त लाभ मध्यावधि कारक हैं
- एपोटेक्स अधिग्रहण और अगले चार वर्षों के दौरान पेश होने वाले 200 से ज्यादा उत्पादों के प्रवाह से यूरोपीय बिक्री में सुधार आने से राजस्व वृद्धि को मदद मिलेगी
- अमेरिका में नई पेशकशों और प्रमुख व्यावसायिक दबाव की भरपाई के लिए इंजेक्टीबल की बिक्री की संभावना
- हालांकि कुल कर्ज अल्पावधि में बढ़ने की आशंका है, लेकिन कर्ज स्तर आधार व्यवसाय से मजबूत आय को देखते हुए सहज स्थिति में है
- हालांकि अनुपालन संबंधित समस्याएं बरकरार रहेंगी, लेकिन मूल्यांकन में इसका असर दिख चुका है

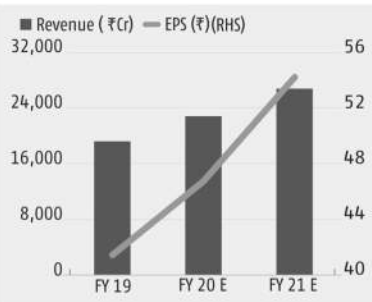

शोभा लिमिटेड

मौजूदा भाव (रु.)	450.8
कीमत लक्ष्य (रु.)	586.3
तेजी (%)	30.1
पीई वर्ष 2021ई (एक्स)	11.7

- बेंगलूरु के बाजार में मजबूत मांग, नई पेशकशों और क्षेत्र में समेकन सकारात्मक हैं
- पिछले साल की रिकॉर्ड बिक्री के बाद, कंपनी द्वारा विभिन्न बाजारों में पेशकशों की मदद से बिक्री की मजबूत रफ्तार बरकरार रखे जाने की संभावना है
- बेंगलूरु, चेन्नई, कोच्चि और पुणे जैसे शहरों में 20.3 करोड़ वर्ग फुट की भूमि से भविष्य में पैसा कमाने में मदद मिल सकेगी
- संविदा सेगमेंट, इंटीरियर और कंक्रीट उत्पादों जैसे विविधीकृत व्यवसाय राजस्व के मुख्य नए स्रोत हैं

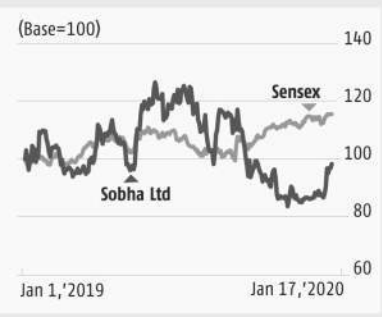

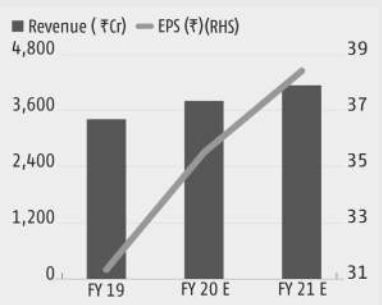

आईएफबी इंडस्ट्रीज

मौजूदा भाव (रु.)	676.6
कीमत लक्ष्य (रु.)	1062.0
तेजी (%)	57.0
पीई वर्ष 2021ई (एक्स)	20.1

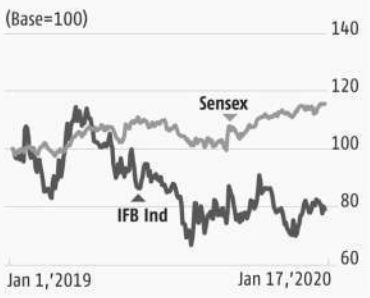

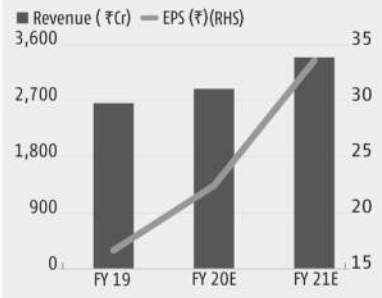

- आईएफबी फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन सेगमेंट में बाजार दिग्गज है। इस सेगमेंट का उसके राजस्व में 51 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान है
- टॉप-लोड वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और एयर कंडीशनर्स जैसे उत्पादों का उसकी कुल बिक्री में 3-16 प्रतिशत का योगदान है
- भविष्य में वृद्धि की वाहक एयर कंडीशनर्स के लिए गोवा में 150 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जा रही निर्माण इकाई होगी
- कलपुर्जों के स्थानीयकरण से वॉशिंग मशीनों में आयात कलपुर्जों में कमी आने का अनुमान है

सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स

मौजूदा भाव (रु.)	170.1
कीमत लक्ष्य (रु.)	209.0
तेजी (%)	22.9
पीई वर्ष 2021ई (एक्स)	15.7

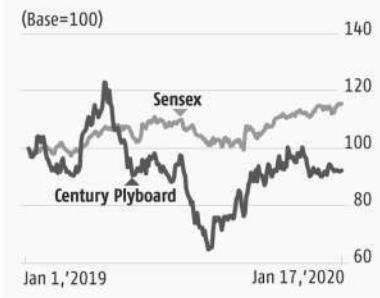

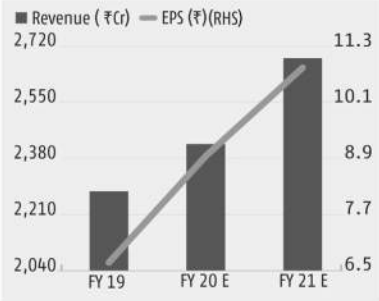

- प्लाईवुड व्यवसाय पर चुनौतीपूर्ण परिवेश से दबाव पैदा होने के बावजूद लैमिनेट, पार्टीकल बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फायरबोर्ड (एमडीएफ) जैसे अन्य प्रमुख सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन अच्छा संकेत है
- कंपनी नई एमडीएफ एवं पार्टीकल बोर्ड इकाई के लिए पूंजीगत खर्च योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है, जिससे उसके दीर्घावधि वृद्धि के परिदृश्य में सुधार आया है
- डीलरों समेत असंगठित कंपनियों पर नियामकीय दबाव से संगठित क्षेत्र को बाजार भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है
- कमजोर उत्पादन लागत से परिचालन आय में सुधार लाने में मदद मिल सकती है

क्वेस कॉर्प

मौजूदा भाव (रु.)	565.0
कीमत लक्ष्य (रु.)	669.6
तेजी (%)	18.5
पीई वर्ष 2021ई (एक्स)	20.3

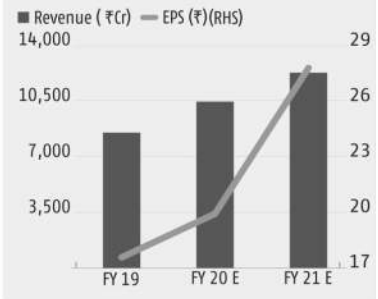

- देश में इस प्रमुख समेकित व्यवसाय सेवा प्रदाता की 9 देशों में उपस्थिति है
- बैलेंस शीट की जटिल स्थिति को लेकर चिंता, रकम के बट्टे खाते से संबंधित कुछ दबाव आदि से पिछले एक साल के दौरान इस शेयर में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है
- आगामी संभावनाओं को देखते हुए विश्लेषकों ने जनरल स्टाफिंग, स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट से राजस्व अगले पांच साल में तीन गुना हो जाने का अनुमान है
- बिक्री में 30 प्रतिशत का योगदान देने वाले स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग सेगमेंट में उपस्थिति से कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल में सुधार आने का अनुमान है

वीआईपी इंडस्ट्रीज

मौजूदा भाव (रु.)	464.7
कीमत लक्ष्य (रु.)	534.9
तेजी (%)	15.1
पीई 2021ई (एक्स)	29.8

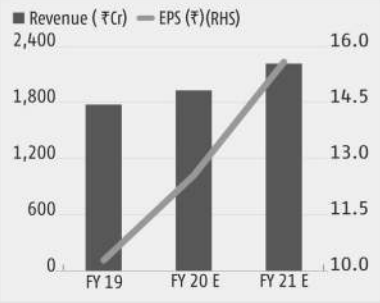

- भारत के ट्रैवल एवं पर्यटन उद्योग के लिए प्रतिनिधि के तौर पर वीआईपी ने संगठित लगेज निर्माताओं के बीच 46 प्रतिशत की बाजार भागीदारी हासिल की है, जिससे वह भारत में सबसे बड़ी और दुनियाभर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है
- वीआईपी के मजबूत आकार ने उसे कच्चा माल लागत-किफायती ढंग से खरीदने, ब्रांडिंग पर खर्च करने और मजबूत ब्रांड पहचान की मदद से नए उत्पाद पेश करने में सक्षम बनाया है
- बांग्लादेश संयंत्र से खासकर सॉफ्ट लगेज के लिए चीन से आयात के मुकाबले लागत को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी
- इससे उसे मुनाफा वित्त वर्ष 2019 के 12.6 प्रतिशत से बढ़ाकर अगले दो साल में 17-18 प्रतिशत करने में मदद मिलेगी

कल्पतरु पावर

मौजूदा भाव (रु.)	445.4
कीमत लक्ष्य (रु.)	611.7
तेजी (%)	37.3
पीई 2021ई (एक्स)	11.0

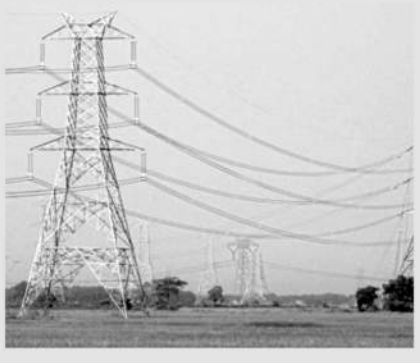

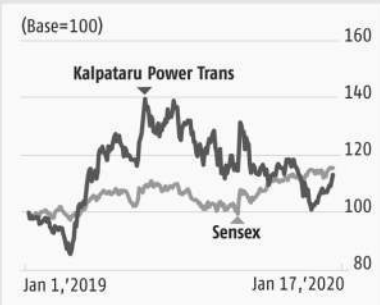

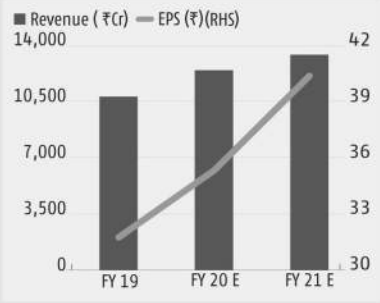

- कंपनी विद्युत पारेषण एवं वितरण क्षेत्र के लिए टर्नकी सॉल्युशन मुहैया करा रही है
- 24,000 करोड़ रुपये से अधिक के साथ कल्पतरू की मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति सकारात्मक है
- उसके दो-तिहाई ऑर्डर प्रवाह (वित्त वर्ष 2020 के लिए 900 करोड़ रुपये) अनुमान पूरा हो चुका है, अन्य मझोली कंपनियों के विपरीत वृद्धि को लेकर चिंता नहीं है
- पारेषण व्यवसाय पर ध्यान दिए जाने के साथ सुधरते पूंजी आवंटन से अगले 6-12 महीनों में शेयर की रेटिंग में बदलाव देखा जा सकता है
- हालांकि मूल्यांकन उचित है, पर प्रवर्तकों द्वारा रियल एस्टेट निवेश और 41 प्रतिशत गिरवी शेयरों को लेकर गतिरोध बना रह सकता है

मौजूदा भाव 17 जनवरी 2020 के हैं, कीमत लक्ष्य और तेजी के आंकड़े अगले 12 महीनों के लिए हैं, ईपीएस प्रति शेयर आय है, पीई वित्त वर्ष2021 के लिए अनुमानों पर आधारित कीमत आय अनुपात है

आंकड़े बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा एकत्रित

फ्लिपकार्ट में रोबोट की फौज

कंपनी आपूर्ति शृंखला को स्वचालित बनाने और 20 करोड़ अतिरिक्त ग्राहकों तक पहुंच के लिए कर रही रोबोट का उपयोग

पीरजादा अबरार

बेंगलूरु के बाहरी इलाके में ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट का एक केंद्र है जहां सामान की छंटनी की जाती है और आगे ग्राहकों के लिए भेजा जाता है। हैंगर के आकार की इस इमारत में जाने पर आप मशीनों की आवाज सुन सकते हैं। ये हजारों की संख्या में काम कर रहे रोबोट (जिन्हें कोबोट कहा जाता है) की आवाज है जो यहां कर्मियों के साथ साथ काम कर रहे हैं।

कर्मी नारंगी रंग के रोबोट पर उत्पाद रखते हैं और कोबोट प्रत्येक पार्सल पर लिखी जानकारी पढ़कर उन्हें अलग अलग करके आवश्यक जगह पर रख देते हैं। यहां काम कर रहे हजारों कर्मचारियों में से एक नकुल पूंजी कहते हैं, 'इनके साथ काम करना शानदार है।'

पहले पूंजी ग्राहक द्वारा ऑर्डर करने वाले सामान को उठाकर उसे अलग करते थे और वापस उस जगह पर जाते थे जहां सामान रखे हुए हैं। विभिन्न स्थानों के लिए सामान भेजने के क्रम में वे घंटों इधर से उधर जाते थे। पूंजी के साथ काम करने वाले ललित मांझी कहते हैं, 'मुझे फिलहाल तकनीकी उपकरणों के साथ काम करते हुए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।'

ऑनलाइन 20 लाख अतिरिक्त ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही फ्लिपकार्ट तकनीक के बढ़ते प्रयोग के बीच रोबोट पर दांव लगा रही है। फिलहाल कंपनी 80 से अधिक श्रेणियों में देश के सभी 20,000 पिनकोड पर अपनी सेवाएं दे रही है।

फ्लिपकार्ट में रोबोटिक्स के प्रमुख प्रणव सक्सेना कहते हैं, 'अगर आप कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो पैकेजों की छंटनी में लगने वाले समय को घटाना होगा। मानवीय तरीके से इस काम को करने में गलती होने की भी संभावना बनी रहती है। कोबोट को इस्तेमाल करने के पीछे विचार यह है कि यह बड़े पैमाने पर काम करेंगे जिससे ग्राहकों को तेज सेवा मिलेगी।'

पिछले वर्ष प्रायोगिक परियोजना के तौर पर रोबोट का इस्तेमाल शुरू करने वाली कंपनी ने बेंगलूरु के सुकोया रोड स्थित फैसिलिटी केंद्र में उनकी संख्या शुरुआत के 450 से चार गुना बढ़ा दी है। मूल रूप से स्वचालित निर्देशित वाहन (एजीवी) रोबोट प्रति घंटे 18,000 पैकेजों की छंटनी कर सकते हैं। वे चौबीसों घंटे काम करने में सक्षम हैं और अपनी बैटरी खत्म होने पर अलग-अलग चार्जिंग प्वाइंट पर खुद को चार्ज करते हैं। फ्लिपकार्ट के अनुसार, ये एजीवी या कोबोट्स आसानी से एक काम से दूसरे काम में लगाए जा सकते हैं। इससे कंपनी को बिग बिलियन डे जैसे समय में बेहतर सेवा देने में आसानी होती है।

रोबोट के काम

- बेंगलूरु इकाई में 450 रोबोट करते हैं काम
- ये रोबोट 1,000 इंसानों के बराबर काम को देते हैं अंजाम
- वे एक घंटे में 18,000 पैकेज की कर सकते हैं छंटनी
- एक दूसरे से करते हैं रियल टाइम में बात
- काम के वितरण, एक दूसरे से टकराव का रखते हैं ध्यान

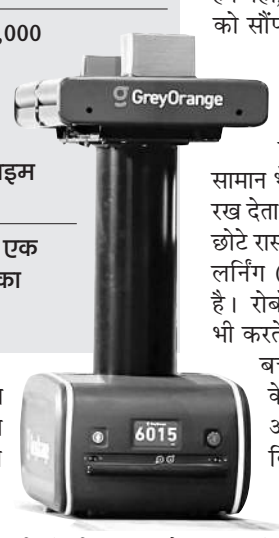

सक्सेना कहते हैं, 'जब आप तेजी से प्रसार करते हैं तो ऐसे समय में स्केलिंग अनेक तरह की समस्या पैदा करती है। विशेषकर, ऐसे समय में जब आपको इस बात की जानकारी न हो कि आपका कितना विस्तार होगा। उदाहरण के लिए, तीन साल पहले आपको नहीं पता था कि लोग कपड़ों की ज्यादा खरीदारी करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की। इन सबके प्रबंधन के लिए आपको सेवाओं में लचीलापन लाने की जरूरत होती है और रोबोटिक्स इसमें अहम भूमिका निभाता है।'

ऑर्डर की छंटनी करने वाली फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी का आकार फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है और इसमें दो फ्लोर हैं। एक कर्मी प्रत्येक पैकेज को स्कैन करता है और इसे उचित स्थान पर भेजने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है। वहां, एक अन्य कर्मी इसे रोबोट को सौंप देता है जो सामान पर लिखे बारकोड को पढ़ने के लिए इसे स्कैनिंग मशीन तक लेकर जाता है। इसमें लिखी जानकारी के हिसाब से रोबोट संबंधित पिनकोड पर सामान भेजने से जुड़े स्थान पर लेजाकर सामान रख देता है। उस स्थान तक जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते का पता लगाने के लिए रोबोट मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीक का प्रयोग करता है। रोबोट एक दूसरे से रियल टाइम में संवाद भी करते हैं, चाहे वह एक दूसरे से टकराने से बचने के लिए हो या सामान के वितरण के लिए। फ्लिपकार्ट में वरिष्ठ प्रबंधक और कंपनी की ऑटोमेशन, शोध एवं विकास टीम का हिस्सा रहे निखिल वर्तक कहते हैं, 'रोबोट की मदद से हम 99.9 प्रतिशत सटीकता के स्तर पर पहुंच गए हैं।'

काम पर जाने से पहले रोबोट नियंत्रित करने वाले कर्मियों को कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होता है। ऑटोमेशन क्षेत्र में कर्मियों को सुरक्षा हेलमेट, जैकेट और जूते पहना जरूरी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लिपकार्ट में रोबोट का उपयोग आपूर्ति शृंखला के स्वचालन की दिशा में अहम कदम साबित होगा। प्रबंधन सलाहकार फर्म प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस में एसोसिएट वाइस प्रेसीडेंट अश्विन कृष्णमूर्ति कहते हैं, 'भारत में कंपनियों ने रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वॉलमार्ट द्वारा रोबोटिक्स स्टार्टअप के अधिग्रण से फ्लिपकार्ट को काफी मदद मिल रही है और कोबोट की मदद से सामान छांटने की दक्षता में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।'

किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी के लिए वेयरहाउस और आपूर्ति शृंखला सबसे जटिल पायदान होते हैं। ईवाई इंडिया में ई-कॉमर्स एवं उपभोक्ता इंटरनेट के लीडर तथा पार्टनर अंकुर पहवा के अनुसार अब ये कंपनियां खरीदारी वाले दिन या मात्र 4 घंटे में डिलिवरी जैसे उपायों पर काम कर रही हैं और इसके लिए कंपनियों को लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग तथा आपूर्ति शृंखला पर काफी ध्यान देना होगा। वह कहते हैं, 'वेयरहाउस में रोबोटिक्स का उपयोग करने से प्रदर्शन क्षमता में 5-10 गुना तक की बढ़ोतरी होती है। ऑनलाइन खरीदारी कारोबार में तेजी लाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए वेयरहाउस में इस उन्नतक तकनीक का उपयोग और कुशल मानव श्रम को उन्नत बनाना काफी अहम है।' दूसरे वैश्विक बाजारों के साथ भारत भी ड्रोन, स्वचलित वाहन जैसी नई तकनीकों का परीक्षण कर रहा है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। कंपनियां कृत्रिम मेधा (एआई) और एमएल जैसी तकनीकों में भी निवेश कर रही हैं। आपूर्ति शृंखला में एआई के प्रयोग से बेहतर प्रबंधन, उत्पादों की छंटनी और मांग का सटीक अनुमान लगाने में मदद करती है जिससे क्षमता सुधार के साथ साथ ग्राहक संतुष्टि भी बेहतर होती है।

ईवाई के पाहवा कहते हैं, 'एमेजॉन और वॉलमार्ट ने आरएफआईडी तकनीक के साथ ड्रोन विकसित करने में अच्छी प्रगति की है और इसकी मदद से इन्वेंटरी प्रबंधन को स्वचलित करने में मदद मिलेगी। ड्रोन रियल टाइम प्रबंधन और स्टॉक खत्म होने जैसी चुनौतियों का सामना करने में भी अहम योगदान करेंगे।' इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार, भारत में औद्योगिक रोबोटों की बिक्री नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है और अकेले 2018 में उद्योगों में 4,771 रोबोट स्थापित किए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है। सालाना स्तर पर उद्योगों में रोबोट लाए जाने के मामले में भारत दुनिया में 11वें स्थान पर है। हालांकि इनमें से अधिकांश रोबोट दूसरे देशों से खरीदे जाते हैं, लेकिन गुड़गांव स्थित ग्रेऑरेंज भारत में काफी पहले शुरू किए गए ऐसे रोबोटिक्स स्टार्ट-अप में से एक है जो उन्नत रोबोटिक्स सिस्टम को डिजाइन, निर्माण और तैनात करती हैं। ग्रेऑरेंज के रोबोट को महिंद्रा, डेल्हीवरी, डीटीडीसी और पेपरफ्राई जैसी कंपनियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

ऑक्सफर्ड इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर करीब 22.5 लाख रोबोट का उपयोग होता है और पिछले तीन दशक में यह संख्या तीन गुना से भी अधिक बढ़ी है। रुझान बताते हैं कि अगले 20 वर्षों में रोबोट का वैश्विक उपयोग 20 गुना बढ़कर साल 2030 तक 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

एल्गोरिद्म

वेब पहल में कहां हैं भारत के कदम!

भारतीय कारोबारी वेबसाइट पर अधिक पहुंच बनाने के प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार में हथकरघा सामान बनाने वालों से लेकर चेन्नई में टेक्सटाइल आपूर्तिकर्ता तक सभी कारोबारी धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि इंटरनेट के इस युग में कारोबार बढ़ाने के वेबसाइट पर उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। किसी भी कारोबार या सेवा के लिए गूगल सर्च करना आज आम चलन है और अपनी क्षमता के बाहर ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए एक साधन भी है। वर्षों से लाखों छोटे कारोबारी ऑनलाइन आ रहे हैं तथा अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज लॉन्च कर रहे हैं। वेबसाइट की मामूली समझ रखने वाले कारोबारियों के लिए वेबसाइट पेशेवरों का एक पूरा समूह अस्तित्व में आ गया है। इनमें वेब डिजाइनर, डेवलपर्स, डिजिटल एजेंसियां, आईटी सेवा प्रदाता और कोई भी दूसरा ऐसा कारोबार शामिल है जो अन्य व्यवसायों को ऑनलाइन उपस्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। हालांकि, कारोबार की डिजिटल उपस्थिति के मामले में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। 56 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देश में, केवल 50 लाख वेब डोमेन (वेबसाइट) पंजीकृत हैं। अर्थात, देश में डोमेन-इंटरनेट पहुंच अनुपात केवल 0.9 प्रतिशत है जबकि अमेरिका में यह अनुपात 37.6 है। हालांकि यह भी नया अवसर हो सकता है। सलाहकार फर्म जिनोव का अनुमान है कि नए और पुराने, सभी तरह के कारोबारी ऑनलाइ आएंगे जिसके चलते अगले तीन वर्षों में वेब सेवा पेशेवर 75 करोड़ डॉलर कमा सकते हैं। जिनोव के मुख्य कार्याधिकारी परम नटराजन कहते हैं, 'इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, ई-कॉमर्स तथा साइबर सुरक्षा के कारण भारत में एसएमबी द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति, डिजिटल खोज तथा उत्पादकता अनुप्रयोगों के लिए सेवाओं को अपनाने में वृद्धि देखी जाएगी।'

इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के बावजूद नहीं हो सका वेब की पूरी क्षमता का उपयोग

2रा ऐप डाउनलोड में भारत का स्थान (12 अरब ऐप डाउनलोड)

29वां मोबाइल ऐप से राजस्व में भारत की रैंक

17 लाख ऐप संबंधी नौकरियां

49% वेब/मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पर काम कर रहे पेशेवर

5-6 हजार डॉलर वेबसाइट या मोबाइल बनाने में एक बार आने वाला खर्च

शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले डोमेन पंजीकरण में पीछे भारत

देश	डोमेन पहुंच अनुपात (%)	डोमेन संख्या (दस लाख)	इंटरनेट उपयोक्ता (दस लाख)
भारत	0.90	5	560
अमेरिका	37.60	110	293
फ्रांस	6.60	4	60
ऑस्ट्रेलिया	4.80	1	24
ब्रिटेन	4.70	3	63
जापान	5.10	6	119
चीन	2.90	24	829
रूस	1.00	1.1	110

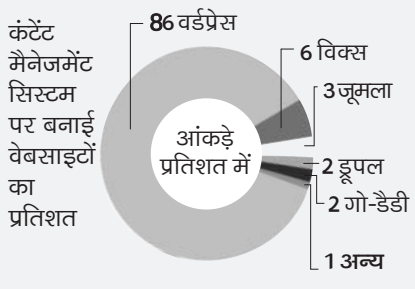

संकलनः युवराज मलिक
स्रोतः एंड्युरेंस इंटरनैशनल ग्रुप और जिनोव रिपोर्ट्स, अन्य

भारत बन रहा रिटेल दिग्गजों की प्रौद्योगिकी रीढ़

वॉलमार्ट लैब्स में करीब 3,700 लोग काम करते हैं और इनमें से अधिकांश बेंगलूरु में हैं

पीरजादा अबरार

वॉलमार्ट की मुहिम

- आईओटी प्लेटफॉर्मः वॉलमार्ट के स्टोरों में फलों और सब्जियों की ताजगी का पता लगाना और उन्हें खराब होने से रोकना
- स्मार्ट पूर्वानुमानः उपभोक्ता प्रोफाइल, स्थानीय रुझानों के आधार पर बिक्री और भंडार का पूर्वानुमान लगाता है
- एआई आधारित सॉल्यूशंसः आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं द्वारा अपलोड किए गए कैटलॉग में गलतियों को दुरुस्त करता है और उनकी गुणवत्ता सुधारता है
- ऑप्टिमाः पिक पाथ ऑप्टमाइजेशन सॉल्यूशन है जो आपूर्ति करने वाले एजेंटों के लिए समय और दूरी कम करता है

बेंगलूरु के बाहरी इलाके में स्थित अमेरिका की खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट का प्रौद्योगिकी केंद्र वॉलमार्ट लैब्स पहली नजर में आसपास की टेक कंपनियों से अलग नहीं दिखता है। इसके भीतर आपको सैकड़ों कर्मचारी अपने कंप्यूटर डैशबोर्ड पर नजरें गड़ाए नजर आएंगे। बेंगलूरु देश में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है और यहां आपको अधिकांश टेक कंपनियों में ऐसे ही नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन वॉलमार्ट लैब्स के कर्मचारी जो कर रहे हैं वह अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों की तरह सामान्य नहीं है।

वे अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में फैले 4,700 से अधिक स्टोरों इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओसी) आधारित एप्लायंसेज में अनियमितताओं का पता लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में किसी स्टोर में किसी फ्रिज के तापमान में बदलाव आता है और वह फलों, सब्जियों या मांस के अनुकूल नहीं होता है, तो वॉलमार्ट लैब्स में बैठे इंजीनियरों को तुरंत इसका अलर्ट मिलता है और वे बेंगलूरु से ही हजारों मील दूर अमेरिका में इस तापमान को दुरुस्त कर देते हैं।

कनेक्टेड स्टोर्स प्लेटफॉर्म विभिन्न उपकरणों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए आईओटी तकनीक का इस्तेमाल करता है। वॉलमार्ट लैब्स में इस प्लेटफॉर्म के अलावा कई वैश्विक इनोवेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें फलों और सब्जियों की ताजगी की जांच, ऊर्जा की खपत में कमी और हर स्टोर की जरूरत का अनुमान लगाना शामिल है। साथ ही वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स और आईओटी जैसी तकनीक के इस्तेमाल से आपूर्ति वाहन की स्थिति पर नजर रखते हैं। वॉलमार्ट का अमेरिका के बाहर यह इस तरह का तीसरा केंद्र है। इस केंद्र के प्रमुख और वॉलमार्ट लैब्स इंडिया के उपाध्यक्ष-प्रौद्योगिकी हरि वासुदेव ने कहा, 'बेंगलूरु के केंद्र का कारोबार पर प्रत्यक्ष असर दिखना शुरू हो गया है, चाहे वह आपूर्ति शृंखला हो, मर्केंडाइजिंग, डेटा एनालिटिक्स या उपभोक्ता अनुभव। प्रौद्योगिकी से वॉलमार्ट को काफी फायदा होने जा रहा है और इससे उपभोक्ताओं को आपूर्ति का बेहतर अनुभव मिल रहा है। इसमें यह लैब अहम भूमिका अदा कर रही है और दुनियाभर में विभिन्न टीमों के साथ समन्वय कर रही है।' भारत में वॉलमार्ट लैब्स में करीब 3700 लोग हैं और इनमें से अधिकांश बेंगलूरु में हैं। वॉलमार्ट लैब्स में जो नई-नई चीजें विकसित की जा रही हैं, उनमें से अधिकांश यहां के कर्मचारियों के दिमाग की ही उपज हैं।

उदाहरण के लिए बेंगलूरु वॉलमार्ट लैब्स के एक कर्मचारी श्रीजित श्रीधरन ने दो साल पहले अमेरिका के एक बिज़नेस दौरे में देखा कि वॉलमार्ट के स्टोरों के भीतर लगे सेंसरों में एकत्र हुए आंकड़ों का इस्तेमाल केवल स्टोर स्तर पर ही किया जा रहा है। इससे उन्हें उपकरणों के लिए एक साझा आईओटी प्लेटफॉर्म बनाने और इसके जरिये अमेरिका के सभी वॉलमार्ट स्टोरों को जोड़ने का विचार आया। उन्होंने लीडरशिप टीम के समक्ष यह विचार रखा जिसने तुरंत इसे मंजूर कर लिया और इसके लिए जरूरी फंड की भी व्यवस्था कर दी। वॉलमार्ट लैब्स में श्रीधरन और दूसरे इंजीनियर किस व्यापक स्तर की समस्या का समाधान खोजने में लगे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के 4,700 वॉलमार्ट स्टोरों में हरेक में औसतन 1,500 सेंसर लगे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को हर दिन 1.5 अरब से अधिक डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करना होगा। एक लचीली व्यवस्था बनाने और प्रोग्राम को जल्दी पूरा करने के लिए, वॉलमार्ट लैब्स के इंजीनियरों ने आईओटी प्लेटफॉर्म के लिए डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को क्लाउड पर डाल दिया। इस तरह नींव से आईओटी प्लेटफॉर्म बनाकर वे उच्च स्तर की सटीकता हासिल करने में सफल रहे और इससे तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम हो गई। साथ ही वॉलमार्ट के केंद्रों में लगे स्मार्ट उपकरणों और सेंसरों से रियल टाइम डेटा एकत्र करके आईओटी प्लेटफॉर्म निगरानी और रिएक्टिव तथा प्रीडिक्टिव रखरखाव क्षमताओं को सक्षम बनाता है। इससे न केवल स्टोर का कामकाज सुगम बनता है बल्कि यह खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम करता है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है ताकि कंपनी वैश्विक ऊर्जा खपत मानकों पर खरी उतर सके।

> इमेज रिकॉग्निशन और एआई आधारित सॉल्यूशन उत्पादों की गुणत्ता सुधारने और कमियों की पहचान के लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए काम करता है

वॉलमार्ट साथ ही ऑनलाइन ऑर्डर को पूरा करने के लिए भी अपने स्टोर का इस्तेमाल कर रही है। यह ऑनलाइन परचून का सामान खरीदने वाले ग्राहकों को अपना ऑर्डर उठाने या लास्ट माइल डिलिवरी नेटवर्क के जरिये इसकी आपूर्ति का विकल्प दे रही है। इसका मकसद स्टोर पर प्रतीक्षा का समय कम करना और उत्पादों की आपूर्ति के लिए अपेक्षित समय की सटीकता 95 फीसदी से ऊपर रखना है।

इसके लिए वॉलमार्ट लैब्स ने पिक पाथ ऑप्टमाइजेशन सॉल्यूशन 'ऑप्टिमा' विकसित किया है। यह कुल समय और स्टोर से ऑर्डर उठाने के लिए स्टोर एसोसिएट द्वारा तय की जाने वाली दूरी में कटौती के लिए विभिन्न तरह के अलगॉरिद्म का इस्तेमाल करता है। यह एक अहम इनोवेशन है क्योंकि एक सप्ताह में वॉलमार्ट के स्टोरों से सामान उठाने में करीब 120,000 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है जो पृथ्वी के व्यास से दस गुना अधिक है। भारतीय टीम गलतियों को दुरुस्त करने और आपूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं द्वारा वॉलमार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किए गए लाखों कैटलॉग की गुणवत्ता को दुरुस्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रही है। इनमें नकली सामान की शिनाख्त करना और कैटलॉग के मुताबिक उत्पादों के रंग, आकार तथा वजन का मिलान करना शामिल है। इतना ही नहीं, वॉलमार्ट की कीमत और प्रतिस्पर्द्धा बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की मदद से मर्केंडाइजर उत्पादों की कीमतों का प्रबंधन करते हैं। इसमें प्रतिस्पद्धियों और अन्य स्थानीय तथा राष्ट्रीय रुझानों से संकेत लेना और मूल्य निर्धारण रणनीति में मदद के लिए डेटा विज्ञान मॉडलों का लाभ उठाना शामिल है।

वॉलमार्ट ने साथ ही स्मार्ट फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। यह सुनिश्चित करता है कि स्टोर पर पर्याप्त मात्रा में सामान का भंडारण हो। यह बिक्री के इतिहास, सीजन, उपभोक्ताओं के खरीदारी रुझानों और हर स्टोर पर मौजूद सामान के आधार पर यह तय करता है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म बर्बादी रोकने में बहुत अहम साबित हुआ है और इससे अमेरिकी स्टोरों में लाखों डॉलर की बचत हुई है।

प्रबंधन सलाहकार कंपनी प्रैक्सिस ग्लोबल एलायंस के निदेशक आर्यमन टंडन के मुताबिक कई फॉच्यून 500 कंपनियां भारत में शोध एवं विकास केंद्र स्थापित कर रही हैं या उनका विस्तार कर रही हैं। इसका मकसद प्रौद्योगिकी में भारत की प्रतिभा का लाभ उठाना है। इनमें खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। टंडन ने कहा, 'स्टार्ट अप कंपनियों के बढ़ने से भारत दुनिया को कम लोग में प्रौद्योगिकी प्रतिभाएं मुहैया करा रहा है। वॉलमार्ट लैब्स भारत में सही दिशा में आगे बढ़ रही है और यह आने वाले समय के वॉलमार्ट के लिए आगे रणनीतिक रास्ता है।'

वॉलमार्ट के अलावा अमेरिका की खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टारगेट और ब्रिटेन की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन टेस्को भी भारतीय प्रौद्योगिकी पर बड़ा दाव खेल रही हैं। देश में टेस्को की प्रौद्योगिकी टीम परंपरागत सेवा आपूर्ति मॉडल से इंजीनियरिंग संस्था में तब्दील हो गई है। बेंगलूरु में टेस्को बिज़नेस सर्विसेज के मुख्य कार्याधिकारी सुमित मित्रा ने कहा, 'यहां काम कर रहे 78 फीसदी सहयोगी प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। वे अनुबंध मुक्त खरीदारी, डेटा विज्ञान या पार्टनरशिप में ऑटोमैटेड वितरण जैसी नई प्रौद्योगिकियों में हमारी वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिभाओं के साथ काम कर रहे हैं। इसके हमें बाजार में अपना अलग मुकाम बनाने में मदद मिलती है और हमें अपने खरीदारों को रोज बेहतर सेवाएं देने का मौका मिलता है।'

बेंगलूरु में टेस्को नई प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही है जिससे रिटेलरों को मैन्युअल इन स्टोर तरीके के बजाय 10 मिनट तेजी से ऑर्डर लेने और प्रोसेस करने में मदद मिलती है।

मकान खरीदने जाएं तो संयुक्त ऋण का लाभ उठाएं

ऋण लेने की पात्रता में बढ़ोतरी के अलावा कर के फायदे भी दोगुने हो जाएंगे

सर्वजित के सेन

पेशे से इंजीनियर आदित्य नित्सुरे 40 साल के हैं और निजी क्षेत्र में काम करने वाली उनकी पत्नी स्मिता बर्वे की उम्र 37 साल है। दोनों ने संपत्ति खरीदने के लिए मिल-जुलकर 2013 में एआईसी हाउसिंग फाइनैंस से आवास ऋण लिया। उन्होंने ब्याज दर कम रखने के फेर में संयुक्त ऋण लिया था। नित्सुरे बताते हैं, '44 लाख रुपये के संयुक्त ऋण पर उस समय 10 फीसदी ब्याज दर बताई गई थी, जो वास्तव में कम थी। इस समय दर 9.5 फीसदी है। साथ में आवेदन करने से हमारी ऋण लेने की पात्रता बढ़ गई थी।' हालांकि नित्सुरे और बर्वे को कम ब्याज दर पर ऋण मिल गया, लेकिन आम तौर पर पति-पत्नी साथ मिलकर कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे उनकी कर्ज लेने की पात्रता बढ़ जाती है यानी उन्हें कर्ज आसानी से मिल जाता है और ज्यादा मिल जाता है। इससे परिवार बड़ा और बेहतर जगह पर बना घर खरीद पाता है। इसलिए अगर आप युवा दंपती हैं, दोनों कमाते हैं और घर खरीदना चाहते हैं तो पति/पत्नी की आमदनी को एक साथ जोड़ना काफी फायदेमंद होता है। बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा, 'रियल एस्टेट खरीदने में अच्छी खासी रकम लगती है और जिन परिवारों में केवल एक व्यक्ति कमाता है, उनमें से कुछ परिवार घर नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन अगर पति या पत्नी को कर्ज लेने में शामिल कर लिया जाए तो दोनों की संयुक्त आय और व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर की बदौलत कम ब्याज दरों पर ऋण पाना मुमकिन हो जाता है।' मगर आवास ऋण को लौटाने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को वित्तीय अनुशासन जरूर बरतना पड़ता है। इस दौरान ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं, जिनका कर्ज लेने वाले व्यक्ति पर असर पड़ता है। मगर संयुक्त ऋण के फायदे बहुत ज्यादा हैं। कुछ अहम फायदे इस तरह हैं:

ज्यादा ऋण

यह फायदा सबसे पहले नजर आता है। जब आप संयुक्त रूप से किसी ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी ऋण लेने की पात्रता बढ़ जाती है। इसलिए ऋणदाता पति और पत्नी दोनों की आमदनी को एक साथ जोड़कर ऋण की ज्यादा राशि स्वीकृत कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप 1 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदना चाहते हैं और आपको 20 साल के लिए 80 लाख रुपये के ऋण की जरूरत है। ऐसे में 8.5 फीसदी ब्याज दर पर समान मासिक किस्त (ईएमआई) करीब 70,000 रुपये होगी। आम तौर पर बैंक हाथ में आने वाले वेतन की 50 फीसदी राशि की ईएमआई को ही मंजूरी देते हैं। ऐसे में आपकी आमदनी 1.4 लाख रुपये प्रति माह (कर एवं अन्य लाभों के बाद) होनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी भी कमाती हैं तो उनका वेतन कर्ज लेने में मददगार बन सकता है। आप ज्यादा ऋण लेकर बेहतर और ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं, भले ही आपकी व्यक्तिगत रूप से आमदनी कम हो।

कर्ज की जल्द अदायगी

अगर आप पति या पत्नी के साथ मिलकर कर्ज लेते हैं तो उसे जल्दी लौटाने की संभावना रहती है। कर्ज की रकम तय अवधि से पहले चुकाने (प्री-पेमेंट) पर किसी तरह की शर्त नहीं जुड़ी है तो व्यक्ति कर्ज लौटाने के लिए अपने पास मौजूद हरेक विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। पति या पत्नी अपने बोनस, नियोक्ताओं से मिलने वाले वैरिएबल भुगतान और आमदनी के अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्री-पेमेंट कर सकते हैं। इससे उनका कर्ज जल्दी चुक जाता है और उन्हें ब्याज का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।

महिलाओं के लिए रजिस्ट्री सस्ती

बहुत से बैंक महिला आवेदकों को कम ब्याज दरों पर कर्ज दे देते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में घर या फ्लैट का पंजीकरण यानी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने पर स्टांप शुल्क भी कम लगता है। हर राज्य में स्टांप शुल्क की दर अलग-अलग है। माईमनीमंत्रा डॉट कॉम के संस्थापक और प्रबंध निदेशक राज खोसला ने कहा, 'संयुक्त आवास ऋण में पत्नी को मुख्य आवेदक बनाकर आप कुल खर्च में काफी बचत कर सकते हैं। आप आवास ऋण पर ब्याज दर और संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में रियायत का लाभ उठा सकते हैं।'

कर लाभ

संयुक्त ऋण लेने वाले पति-पत्नी को कर रियायत का भी लाभ मिलता है। पति-पत्नी दोनों संयुक्त रूप से 7 लाख रुपये तक का कर लाभ हासिल कर सकते हैं। इसमें धारा 80 सी के तहत तीन लाख रुपये (प्रत्येक के लिए 1.5 लाख रुपये की कटौती) और धारा 24 (बी) के तहत ब्याज भुगतान पर चार लाख रुपये (प्रत्येक के लिए दो लाख) का कर लाभ शामिल है। हालांकि अपना घर खरीदना हमेशा ही बहुत खुशी का सबब होता है, लेकिन आपको संयुक्त ऋण लेते वक्त कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम पहलू होते हैं।

तलाक या मृत्यु

अगर पति-पत्नी ऋण बकाया होने के दौरान तलाक लेने का फैसला करते हैं तो दोनों को यह ध्यान रखना होगा कि कर्ज उसके बाद भी चुकाना होगा और उसे पूरी तरह चुकाने के तरीके भी उन्हें तलाशने होंगे। शेट्टी बताते हैं, 'बैंक अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए संपत्ति पर कब्जा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर कर्जदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है, इसलिए मिलकर ऋण लेने वाले पति या पत्नी को पहले ही यह साफ कर लेना चाहिए कि अगर भविष्य में उन्हें अलग होना पड़ता है तो वे अपने कर्जों को कैसे संभालेंगे।' पति या पत्नी में से किसी एक की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने की स्थिति में जीवित साथी समय पर किस्तें चुकाने के लिए जिम्मेदार है।

अपनाएं ये नियम

अगर मालिक की ऋण लौटाने की अवधि में मृत्यु हो जाती है तो कानूनी बाध्यताओं से बचने के लिए वसीयतनामा बनाना जरूरी है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि शादी कब तक चलेगी। ऐसे में व्यक्ति प्रॉपर्टी, ऋण लौटाने में हिस्सेदारी और अन्य प्रमुख चीजों के बारे में कानूनी समझौता करने के बारे में विचार कर सकता है। इससे पति या पत्नी को ऋण की अवधि के दौरान तलाक लेने की स्थिति में मदद मिलेगी। व्यक्ति को ऋण लेते समय पर्याप्त ऋण सुरक्षा बीमा भी लेना चाहिए। उन लोगों के लिए बड़ी देनदारियों को कवर करने वाला टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, जिन पर परिवार आश्रित है और उनकी दुर्भाग्यवश मौत होने की स्थिति में परिवार पर देनदारियां आ जाएंगी। बीमा कवर से यह सुनिश्चित होगा कि मृत्यु की स्थिति में आवास ऋण का भार पति या पत्नी पर नहीं पड़े। खोसला की सलाह है, 'आवास ऋण को लौटाने की देनदारी को कवर करने वाला आवास ऋण बीमा खरीदना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा विवाद की स्थिति में देनदारी वितरण के बारे में कानूनी समझौता करें।'

डिफॉल्ट और क्रेडिट स्कोर

कसी भी संयुक्त आवास ऋण में पति और पत्नी दोनों की एकसमान देनदारी और जिम्मेदारी होती है। इसलिए नौकरी जाने जैसी किसी वजह से पति या पत्नी के हिस्से की ईएमआई ऋणदाता के पास नहीं पहुंचती है तो इसे डिफॉल्ट माना जाता है, जिससे दोनों लोगों का क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होता है। शेट्टी कहते हैं, 'सह-आवेदक के रूप में एक दंपती पूरे ऋण के भुगतान की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेता है। एक के डिफॉल्ट करने से दोनों के क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है।'

कैसे हासिल करें निष्क्रिय खाते में पड़ी रकम

बिंदिशा सारंग

बता सकते हैं कि 4.7 करोड़ और 14,307 का क्या मतलब है? ये आंकड़े बैंक खातों के हैं, जिनमें ऐसी रकम पड़ी है, जिस पर किसी ने दावा ही नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक यह रकम भारतीय बैंकों में बेकार पड़ी हुई है और इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं किए गए हैं। नागपुर में रहने वाले प्रमाणित वित्तीय योजनाकार रंजीत दानी का कहना है, 'ऐसे निष्क्रिय या परिचालन से बाहर खाते होने की दो वजहें हैं। पहली वजह नौकरी बदलना है क्योंकि हर नई नौकरी में आपका नया बैंक खाता खुल जाता है। लेकिन पुराने खाते अक्सर बंद नहीं किए जाते और इस्तेमाल भी नहीं किए जाते। कई बार तो सालों तक उनकी याद भी नहीं रहती। दूसरी वजह लोगों का गुजर जाना है। वे लोग जीवित रहते हुए अपने परिजनों को यह बताना भूल जाते हैं कि अमुक बैंकों में उनके खाते हैं।'

अगर आप अपने खाते में 12 महीने से अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं करते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है। यदि आप खाते में 24 महीने तक लेनदेन नहीं करते तो उसे बैंक की भाषा में 'डॉरमैंट' करार दिया जाता है। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डॉरमैंट खातों और निष्क्रिय खातों में किसी तरह का फर्क नहीं होता।

ऐसे डॉरमैंट या निष्क्रिय खातों की अपनी अलग समस्या होती हैं और उनसे कुछ जोखिम भी जुड़े रहते हैं। पहले तो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे खाते में पड़े धन पर केवल 4 फीसदी ब्याज मिलेगा, जो नवंबर के 5.54 फीसदी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी कम है। यदि इसी रकम को पीपीएफ में निवेश किया जाता तो 8.65 फीसदी प्रतिफल हासिल होता। दानी आगाह करते हैं, 'ऐसे खाते बेईमान बैंक कर्मचारियों के लिए आसान शिकार की तरह होते हैं और वे इसमें से धन निकाल सकते हैं। उनका इस्तेमाल काले धन को सफेद बनाने में भी किया जा सकता है।' आखिरी दिक्कत यह है कि बैंक निष्क्रिय खातों को संभालने के एवज में हर साल 250 से 750 रुपये तक लेते हैं। आम तौर पर यह रकम जमा हो रहे ब्याज में से काट ली जाती है। यदि आप न्यूनतम रकम नहीं रख रहे हैं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है।

अपने सभी खर्च पहले वाले खाते से कीजिए और निवेश की जरूरतें दूसरे खाते से पूरी कीजिए

कैसे वापस मिले रकम?

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों के लिए दस साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। बैंकबाजार डॉट कॉम के मुख्य कार्य अधिकारी आदिल शेट्टी समझाते हैं, 'सबसे पहले निष्क्रिय खाते का ब्योरा जांचिए। यदि आपका अपना खाता है तो आपको उस रकम का दावा करने के लिए फॉर्म भरना होगा, जो आपके खाते में पड़ी है। उसके साथ आपको पहचान का वैध प्रमाण और पते का सबूत भी जमा करना होगा। यदि आप खाताधारक के कानूनी वारिस हैं तो आपको दावे के फॉर्म और पहचान एवं पते का सबूत के साथ खाताधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा। ध्यान रहे कि आपको जांच के लिए सभी मूल प्रमाणपत्र भी बैंक के सामने पेश करने होंगे।' बैंक दावे की समीक्षा करेगा और दावा मंजूर होने पर उसे निपटाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाएगा।

दावा नहीं किया तो?

यदि दस साल या उससे ज्यादा समय तक रकम का दावा नहीं किया गया तो रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार यह रकम जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में जमा कर दी जाएगी।

शेट्टी बताते हैं, 'रकम उस कोष में चली गई हो तो भी खाता धारक उसका दावा कर सकते हैं। उस सूरत में उन्हें जो रकम मिलेगी, उसमें खाते में पड़ा धन तो शामिल होगा ही, उस बैंक द्वारा दिया गया ब्याज भी जुड़ा होगा। रकम पर ब्याज जुड़ता रहेगा।' यदि सावधि जमा (एफडी) के परिपक्व होने पर भी दावा नहीं किया गया है तो उस पर परिपक्वता की अवधि के बाद से बचत खाते की दर पर ब्याज मिलेगा। ध्यान रखिए कि बचत बैंक खातों पर ब्याज दिया ही जाता है चाहे बैंक खाता चल रहा हो या निष्क्रिय पड़ा हो। अच्छा तो यही है कि वेतन खाते के अलावा आपके दो से अधिक खाते नहीं हों। ये ही आपके प्राथमिक खाते होंगे। दानी की सलाह है, 'जैसे ही वेतन आपके खाते में आता है, उसे बाकी दोनों बचत खातों में भेज दीजिए। एक खाता खर्च के लिए होगा और दूसरा निवेश खाते के तौर पर चलाइए।' अपने सभी खर्च पहले वाले खाते से कीजिए और निवेश की जरूरतें दूसरे खाते से पूरी कीजिए। दानी कहते हैं कि इस तरह आप अपनी सभी वित्तीय जानकारी भी व्यवस्थित तरीके से रख सकेंगे।

निष्क्रिय खातों में पड़े करोड़ों रुपये

बैंक	खातों की संख्या	रकम (करोड़ रु.)
सार्वजनिक बैंक	4,24,13,775	12,075.71
निजी बैंक	51,29,927	1,851.56
विदेशी बैंक	3,76,213	376.97
लघु वित्त बैंक	29,193	2.43
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	9,030	0.53
योग	4,79,58,138	14,307.19

भारत में उन जमा खातों के आंकड़े, जो 10 साल या अधिक समय से निष्क्रिय हैं। *स्रोतः रिजर्व बैंक*

नकदी की हो इफरात तभी लें आवास ऋण ओवरड्राफ्ट

आवास ऋण ओवरड्राफ्ट सुविधा में अतिरिक्त धन जमा करने से आपको जो बचत होगी, वह आपसे वसूले जा रहे अधिक ब्याज से भी ज्यादा होनी चाहिए

सर्वजीत के सेन

जब आप अपना नया घर खरीदने के लिए कर्ज लेने जाते हैं तो कर्ज देने वाला बैंक या संस्था कर्ज देने के साथ ही आपके सामने आवास ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी रख सकते हैं। अगर आपको यह सुविधा ठीक लग रही है या आप इसे लेने पर विचार कर रहे हैं तो पहले इसके अच्छे-बुरे पहलू अच्छी तरह जांच लेने चाहिए।

ओवरड्राफ्ट की सुविधा में कर्जदार के आवास ऋण खाते को उसके चालू या बचत खाते से जोड़ लिया जाता है। उसके पास जो भी अतिरिक्त रकम होती है, उसे इस जुड़े हुए खाते में डालने की इजाजत दे दी जाती है। जो रकम जमा की गई है अगर वह मासिक किस्त से ज्यादा होती है तौर अतिरिक्त रकम को आवास ऋण का समय-पूर्व भुगतान या प्री-पेमेंट मान लिया जाता है और बकाया मूलधन में से उसे घटा दिया जाता है। जब मूलधन घट जाता है तो ब्याज के रूप में जाने वाली कुल रकम भी कुछ हो जाती है और कर्ज की अवधि में भी कमी आ जाती है।

यह सुविधा काफी लचीली होती है। इसमें कर्जदार जब चाहे जमा की गई रकम निकाल भी सकता है। निकासी की यह सुविधा पैसे की जरूरत पड़ने पर काफी काम आ जाती है। आधार हाउसिंग फाइनैंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी देव शंकर त्रिपाठी समझाते हैं, 'आपने जो भी बचत की है, उसमें से कुछ रकम यदि आप आवास ऋण का अतिरिक्त भुगतान करने में खर्च कर देते हैं तो आपके पास नकदी की कमी हो सकती है। इसलिए अगर आपको जरूरत पड़े तो आप जुड़े हुए यानी लिंक्ड खाते में से वह रकम निकाल सकते हैं। जब आप इस तरह रकम निकालते हैं तो आपके कर्ज का मूलधन वापस सामान्य स्तर पर पहुंच जाता है और आपको पहले जैसी दर पर ही ब्याज देना पड़ता है।'

यह सब तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कर्ज लेने वाले को यह भी पता होना चाहिए कि इस योजना के नुकसान क्या हैं। अगर आप ओवरड्राफ्ट सुविधा वाला आवास ऋण लेते हैं तो आपको सामान्य आवास ऋण की ब्याज दर के मुकाबले 20 से 50 आधार अंक अधिक दर पर ब्याज चुकाना पड़ सकता है। पैसाबाजार डॉट कॉम के आवास ऋण प्रमुख रतन चौधरी की राय है, 'यह सुविधा चुननी है तो खर्च और लाभ का विश्लेषण कर लीजिए: अपने पास पड़ी अतिरिक्त रकम आवास ऋण के ओवरड्राफ्ट खाते में डालकर ब्याज पर होने वाले खर्च में आप जो बचत कर रहे हैं, वह इस ऋण की ऊंची ब्याज दर के कारण हो रहे खर्च से अधिक है या नहीं?'

आवास ऋण का मूलधन चुकाने पर किसी भी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला व्यक्ति ओवरड्राफ्ट सुविधा वाले खाते में अतिरिक्त रकम डाल देता है तो आयकर अधिनियम के तहत उसे चुकाए जा रहे मूलधन में शामिल नहीं किया जाता है और उस व्यक्ति को इस पर कर कटौती का लाभ भी नहीं मिलता है।

जो मंझे हुए निवेशक हैं यानी जिन्हें सही जगह निवेश करने और अच्छी रकम कमाने का तरीका आता है, वे अपनी अतिरिक्त बचत को लिंक्ड खाते में जमा करने के बजाय किसी ऐसी वित्तीय योजना में लगा सकते हैं, जिससे उन्हें और भी अच्छा प्रतिफल हासिल हो। त्रिपाठी की भी यही राय है। वह कहते हैं, 'यदि आप अपनी अतिरिक्त रकम को किसी अन्य संपत्ति में निवेश कर अधिक प्रतिफल हासिल कर सकते हैं तो उसे आवास ऋण चुकाने में इस्तेमाल करना नुकसानदेह ही होगा।'

आवास ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा स्वरोजगार वाले लोगों या कारोबारियों के लिए सबसे अच्छी है क्योंकि उनके पास नकदी की आमद घटती-बढ़ती रहती है यानी वेतनभोगियों की तरह उन्हें हर महीने एकसमान रकम नहीं मिलती। जिन वेतनभोगी व्यक्तियों को बोनस के रूप में मोटी रकम मिलती है या इन्सेंटिव की रकम एकमुश्त दी जाती है, वे भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। चौधरी कहते हैं, 'आवास ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा तभी चुनें, जब आपके पास अक्सर अतिरिक्त रकम आती रहती हो। ऐसा नहीं है तो आपको इस सुविधा के एवज में ब्याज पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी ब्याज दर सामान्य आवास ऋण की ब्याज दर के मुकाबले ज्यादा होती है।'

अगर आप यह योजना चुनने का मन बना रहे हैं तो पहले अपनी दीर्घावधि वित्तीय योजना और बचत की क्षमता को ठीक से आंक लीजिए। त्रिपाठी कहते हैं, 'आवास ऋण की ज्यादा रकम चुकाएंगे तो आपकी नियमित बचत पर असर पड़ सकता है, जो वित्तीय रूप से समझदारी की बात नहीं कहलाएगी। वही कर्ज लंबे अरसे में चुकाएंगे तो आपको भविष्य के लिए रकम बचाने में भी मदद मिलेगी। आवास ऋण को जल्द से जल्द चुकाने के फेर में उन्हें ही पड़ना चाहिए, जो अपने भविष्य के लिए अच्छी खासी बचत पहले ही कर चुके हैं।'

ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लगता है ज्यादा ब्याज

ऋणदाता	सामान्य आवास ऋण	ओवरड्राफ्ट आवास ऋण
भारतीय स्टेट बैंक	8.15-8.8	8.4-9.05
सिटी बैंक	8.17-8.92	8.27-9.02
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.2-8.35	8.45-8.85
बैंक ऑफ बड़ौदा	8.1-9.1	8.1-9.35
एचएसबीसी	8.65-8.75	8.8-9.3
पंजाब नैशनल बैंक	7.95-8.45	8.2-8.7

ब्याज दर (प्रतिशत में), स्रोतः पैसाबाजार डॉट कॉम

- **आवास ऋण का मूलधन चुकाने पर किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिल सकता है**
- **आवास ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा तभी चुनें, जब आपके पास अक्सर अतिरिक्त रकम आती रहती हो**

नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर पर नेताओं के बीच बयानबाजी और टकराव जारी

तमिल शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

निर्मला सीतारमण ने कुछ राज्यों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू न करने के प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक

गिरीश बाबू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा है कि तमिल शरणार्थी भले ही मौजूदा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), 2019 का हिस्सा नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका के 95,000 तमिल शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनका कहना था कि पिछले छह सालों में 2,838 पाकिस्तानी नागरिकों, 912 अफगानी और 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों सहित मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई और ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर चेन्नई सिटिजंस फोरम और न्यू इंडिया फोरम द्वारा आयोजित इवेंट को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि 1964 और 2008 के बीच 4.61 लाख श्रीलंकाई तमिलों को भारतीय नागरिकता दी गई।

नागरिकता संशोधन कानून, 2019 में श्रीलंका के तमिलों को क्यों नहीं शामिल किया गया है इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'कभी-कभी एक खास वर्ग को नागरिकता देने के लिए कानून में संशोधन किया जाता है। जब श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही थी तब आप यह पूछ सकते थे कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता देने पर विचार क्यों नहीं किया गया था। मौजूदा संशोधित कानून में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों का विकल्प नहीं देने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। कानून के ही एक अंश में कुछ संशोधन किया गया है। 95,000 लोग अब भी शरणार्थी शिविरों में हैं। उन्हें भी नागरिकता देने की प्रक्रिया होगी।'

उन्होंने कहा कि सरकार ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को नागरिकता दी है और उनमें मुस्लिम हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कुल 566 मुसलमानों को 2014 से ही नागरिकता दी गई है जिनमें पाकिस्तानी गायक अदनान सामी भी हैं जिन्हें 2016 में नागरिकता मिली है। वर्ष 2016-18 के दौरान 391 अफगानी और 1595 पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई थी। सरकार ने उन लोगों को मुआवजा भी दिया है जो पाकिस्तान से यहां आए थे। सरकार पाकिस्तान से आने वाले लोगों को मुआवजा भी देती रही है।

वर्ष 2014 में पाकिस्तान से आने वाले 36,384 परिवारों को एक बार वित्तीय मदद दी गई थी। वर्ष 2019 में मंत्रिमंडल ने छंब से देश के दूसरे हिस्से में आने वाले और बाद में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जाने वाले 5,300 परिवारों को भी नागरिकता देने का फैसला किया जो पहले मुआवजे से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को जोड़ना सही नहीं है क्योंकि एनआरसी के ब्योरे पर चर्चा नहीं हुई है और न ही उसे अंतिम रूप दिया गया है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं और विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मानना है कि असम में चल रही एनआरसी की प्रक्रिया बाकी देश में भी लागू होगी। असम की एनआरसी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में हो रही है और यह उस क्षेत्र की जरूरत है।'

एससी/एसटी सदस्यों के साथ बैठक तय होने से सीतारमण प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई बैठक में रहीं अनुपस्थित

जम्मू कश्मीर सरकार के आंकड़े के मुताबिक करीब 50,000-1,00,000 कश्मीरी मुस्लिम और 1,50,000-3,00,000 कश्मीरी हिंदू आतंकवाद की वजह से विस्थापित हुए थे। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तीन लाख से ज्यादा लोग देश केविभिन्न राज्यों में गए।

उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि वह राज्यों का दौरा करते हुए नागरिकता संशोधन कानून का ब्योरा दे रही हैं और साथ ही वह केंद्रीय बजट पर भी काम कर रही है जिसे 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित उद्योग बैठक में अनुपस्थित रहने के आरोपों के संदर्भ में कहा कि वह अपना काम कर रही थीं और सरकार के संदेश को आम जनता तक पहुंचा रही थीं जो उनका कर्तव्य भी है। उन्होंने पिछली जुलाई में बजट पेश किए जाने के बावजूद आर्थिक उपायों से जुड़ी घोषणाएं हर शुक्रवार को किए जाने की आलोचना का जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने सभी सेक्टर की बात सुनने के बाद वे घोषणाएं की थीं और उनके मुद्दों का हल करने के लिए वे फैसले लिए थे। उन्होंने कहा, 'बिना कुछ जाने, आधी-अधूरी सूचनाओं के आधार पर विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि मुझे बैठक में बुलाया नहीं गया था। यह बैठक नीति आयोग ने आयोजित की थी और उन्होंने मेरे साथ-साथ सभी को बुलाया था। मैंने कहा था कि मैं बैठक में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी क्योंकि एससी/एसटी सदस्यों, एमएसएमई उद्योग के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मेरी बैठक पहले से ही तय है। इस बैठक की योजना एक-डेढ़ महीने पहले ही तय हो गई थी। क्या मुझे यह कहना चाहिए था कि मैं प्रधानमंत्री की बैठक की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी और वे दिल्ली की ठंड में मेरा इंतजार करें? मेरी पार्टी ऐसी नहीं है।'

देश के आर्थिक हालात को देखते हुए क्या यह वक्त नागरिकता संशोधन कानून के लिए सही था, इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम काफी लंबे समय से लंबित था और विचार यह था कि इसे जितनी जल्दी संभव हो उसे करना है। इसकी चर्चा पार्टी के घोषणापत्र में भी की गई और एक बार कांग्रेस के घोषणापत्र में भी यही एजेंडा था। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकते हैं लेकिन राज्यों का यह कहना संवैधानिक नहीं है कि वे इस कानून पर अमल नहीं करेंगे। सीतारमण ने राज्यों के ऐसे प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया।

फोटोः पीटीआई

चेन्नई में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चेन्नई सिटीजंस फोरम के कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण

...वित्त मंत्री बोलीं

- पिछले 6 सालों में 2,838 पाकिस्तान के नागरिकों, 912 अफगानी और 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों सहित मुसलमानों को नागरिकता दी गई
- श्रीलंका के 95,000 तमिल शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी
- वर्ष 2014 में पाकिस्तान से आने वाले 36,384 परिवारों को एक बार वित्तीय मदद दी गई थी
- शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम काफी लंबे समय से लंबित था

सीएए, एनआरसी भारत का आंतरिक मामला

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को भारत का आंतरिक मामला करार दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून जरूरी नहीं था। नागरिकता संशोधन कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक वहां से भारत आए हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस विवादित कानून के खिलाफ भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। हसीना ने गल्फ न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में भारत के नए नागरिकता कानून के संदर्भ में कहा, 'हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया है। यह जरूरी नहीं था।'

उनका यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमिन के उस बयान के बाद आया है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं, लेकिन इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि वहां किसी भी तरह की अनिश्चितता का पड़ोस पर असर होगा।

अखबार ने कहा कि बांग्लादेश की 16.1 करोड़ आबादी में 10.7 फीसदी हिंदू और 0.6 फीसदी बौद्ध हैं और उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न की वजह से किसी के भी भारत जाने से इनकार किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबु धाबी में हसीना ने यह भी कहा कि भारत से भी लोगों के बांग्लादेश पलायन करने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, 'भारत से कोई प्रवासी वापस नहीं आ रहे हैं लेकिन भारत के अंदर लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।'

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से बार-बार दोहराया है कि एनआरसी भारत की एक अंदरूनी कवायद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अक्टूबर 2019 के मेरे नई दिल्ली के दौरे के दौरान मुझे इसे लेकर आश्वस्त किया था।' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मौजूदा दौर में सर्वश्रेष्ठ हैं और व्यापक क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। *एजेंसियां*

अवसरवादिता से भरी केजरीवाल की प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा एवं जामिया मिल्लिया इस्लामिया तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेंगे और इन मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कमजोर प्रतिक्रिया से अवसरवादिता की बू आती है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी को पर्याप्त सीटें मिल सकती हैं जिनके बल पर वह सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

राज्यसभा सांसद एवं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की चुनाव एवं प्रचार समितियों के सदस्य सिब्बल ने एक साक्षात्कार में कहा, 'वह (केजरीवाल) जामिया में नहीं आए, वह जेएनयू में नहीं आए। उन्होंने पर्याप्त रूप से बार-बार, मजबूत और खुलकर बयान नहीं दिए। आसपास जो कुछ हो रहा है उसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुछ हद तक कमजोर प्रतिक्रिया ने सही संकेत नहीं भेजे हैं।'

यह पूछे जाने पर कि क्या नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर व्यापक हंगामा और विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा चुनाव में बड़ा कारक साबित होंगे, सिब्बल ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'केजरीवाल अभी तक विश्वविद्यालय परिसरों में नहीं गए क्योंकि यह राजनीति है।' सिब्बल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) वोट बैंक चले जाने के डर से सीएए, एनपीआर और एनआरसी के बारे में अधिक बात नहीं कर रही जिसकी उसे सख्त जरूरत है।

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना सकती है, सिब्बल ने कहा, 'हमें ऐसे बड़े दावे करने चाहिए लेकिन हम इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। हमें इतनी पर्याप्त सीटें मिलेंगी कि हम सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।'

सिब्बल ने इन बातों को नकारा कि किसी लोकप्रिय व विश्वसनीय चेहरे के अभाव के कारण चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा। सिब्बल ने कहा, 'हमारे पास 2014 में नरेंद्र मोदी का विश्वसनीय चेहरा था ऐसा भारत के लोगों को लगता था, देखिए तब से क्या हुआ है। आम लोगों का चेहरा, मुख्यमंत्री के चेहरे से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुश्किल स्थिति में है क्योंकि उसने विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मिसाल दी जहां चुनावी विशेषज्ञ गलत साबित हुए हैं।

राज्यों को होगी परेशानी

सिब्बल ने कहा कि राज्य विधानसभाओं को केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन अगर अदालत ने सीएए को संवैधानिक करार दिया तब इस कानून का विरोध करने वाले राज्यों के लिए परेशानी होगी।

हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब तक अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्यों को नागरिकता संशोधन कानून जैसे असंवैधानिक कानून को लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पार्टी ने कहा कि राज्य को केंद्र के साथ असहमत होने का अधिकार है और नागरिकता संशोधन कानून पर गृह मंत्री अमित शाह के बार-बार के बयान और राज्यपालों का इसे लागू करने के लिए राज्यों पर दबाव बनाना संवैधानिक संघवाद के खिलाफ है। *भाषा*

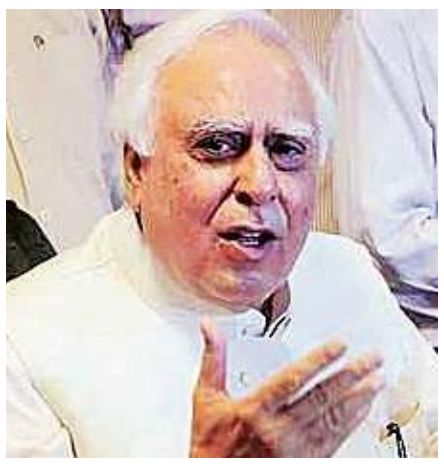

सिब्बल बोले यदि अदालत ने सीएए को संवैधानिक बताया तब इसका विरोध करने वाले राज्यों को होगी परेशानी

- सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर हंगामा, जामिया-जेएनयू हिंसा, दिल्ली चुनाव में मुद्दा
- केजरीवाल की सीएए जेएनयू हिंसा पर धीमी प्रतिक्रिया से अवसरवादिता की बू आती है
- कांग्रेस दिल्ली में सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाएगी
- कांग्रेस ने कहा राज्यों को केंद्र से असहमत होने का अधिकार है। असंवैधानिक कानून लागू करने के लिए बाध्य न करें

मूकदर्शक बनकर नहीं रहूंगा

अदालत में राज्य सरकार की याचिका पर राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट

नागरिकता संशोधन कानून पर केरल की वाम मोर्चे की सरकार के साथ जारी खींचतान की स्थिति के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह मूकदर्शक नहीं बने रहेंगे। उन्होंने कहा, 'यह निजी लड़ाई नहीं है। संविधान और देश का कानून महत्त्वपूर्ण है और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सारे कामकाज संविधान और कानून के अनुरूप ही हों।'

आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सूचना दिए बगैर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने के लिए माकपा नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजभवन कार्यालय ने राज्य के मुख्य सचिव से यह रिपोर्ट मांगी है।

राजभवन के एक शीर्ष सूत्र ने कहा, 'राज्यपाल कार्यालय ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करने के सरकार के कदम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।' एलडीएफ सरकार ने इस कानून के खिलाफ 13 जनवरी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अनुरोध किया था कि इस कानून के संविधान के अनुरूप नहीं होने की घोषणा की जाए।'

खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर हमला बोलते हुए कहा था कि सार्वजनिक कार्य और सरकार के कामकाज को किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की मर्जी के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता और हर किसी को नियम का पालन करना चाहिए। केरल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला और नए कानून को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने वाला पहला राज्य है।

अपनी नाखुशी को सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके राज्यपाल ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा था कि कामकाज के नियम की धारा 34(2) की उपधारा 5 के तहत प्रदेश सरकार को राज्य एवं केंद्र के रिश्तों को प्रभावित करने वालों की जानकारी राज्यपाल को देनी चाहिए। हालांकि, राज्य इस बात पर कायम है कि उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और राज्यपाल कार्यालय की शक्ति को चुनौती देने के लिए जानबूझ कर कोई प्रयास नहीं किए गए। कानून मंत्री ए के बालन ने शनिवार को कहा कि सरकार खान द्वारा उठाए गए सभी संशयों को दूर करेगी। *एजेंसियां*

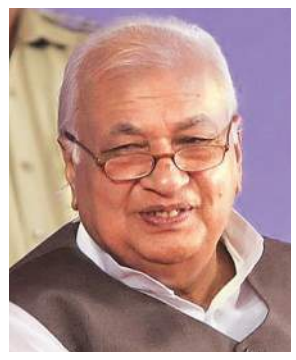

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

लखनऊ में भी महिलाओं का प्रदर्शन जारी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में पुराने लखनऊ में महिलाओं का प्रदर्शन रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया कि यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है और कहा कि इन मुस्लिम महिलाओं को जनता तो दूर अपने परिवार वालों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है।

खुले आसमान के नीचे पिछले शुक्रवार से बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर पुराने लखनऊ स्थित घंटाघर के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ बच्चे भी हैं। इन महिलाओं का कहना है कि सरकार जब तक सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लेती है तब तक वह अपना धरना समाप्त नहीं करेंगी।

इस बीच, भाजपा के प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा कि दिसंबर महीने में सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए ही सपा और कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन प्रायोजित कराया है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि काफी सर्दी होने के बावजूद पुलिस ने देर रात उनके कंबल छीन लिए। हालांकि पुलिस ने एक बयान जारी कर इस पर सफाई दी है।

पुलिस का कहना है कि कुछ सामाजिक संगठन इन महिलाओं को कंबल दे रहे थे तभी बड़ी संख्या में अन्य लोग जो इस धरने में शामिल नहीं थे, वे भी कंबल लेने के लिए वहां पहुंच गए। भीड़ और अफरातफरी को रोकने के लिए उन्होंने वहां से कंबल हटवाए हैं।

भाजपा ने लखनऊ के प्रदर्शन को बताया है प्रायोजित

घर-घर संपर्क

सीएए-एनपीआर-एनआरसी के बीच संबंध के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए माकपा जल्द ही हर घर जाकर जानकारी देगी। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि पूरे देश में यह अभियान चलाया जाएगा। वह केरल में पार्टी की केंद्रीय समिति की तीन दिवसीय बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। केंद्रीय समिति ने अपील की कि लोग एनपीआर के सवालों का जवाब न दें।

राजस्थान में भी प्रस्ताव

कांग्रेस शासित राजस्थान ने 24 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना है। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि सरकार द्वारा विधानसभा में सीएए के खिलाफ लाए जा रहे प्रस्ताव का मजबूती से विरोध करेगी। केरल और पंजाब सीएए के खिलाफ केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि प्रदेश सरकार राज्य में सीएए और एनआरसी लागू नहीं करेगी। *एजेंसियां*